कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QSDI : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

आवरण कथा : जन-आशीर्वाद यात्रा उज्जैन से प्रारंभ

एक रिपोर्ट........ 7

वार्तालाप

पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ श्री मोदी की बातचीत...... 18

लेख

ओसामा बिन लादेन सम्बन्धी पाकिस्तान का न्यायिक आयोग

– **लालकृष्ण आडवाणी**........ 11

कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव का साम्प्रदायिकरण करने की कोशिश क्यों कर रही है

– **अरुण जेटली**........ 13

संकट में फंसो तो बात करो सेक्युलरिज्म की!

–**रविशंकर प्रसाद**........ 20

नीतियों की नाकामी

–**संजय गुप्त**........ 22

बिहार ने दिखाया बच्चों को लूटने का रास्ता

–**कंचन गुप्ता**........ 24

हताश कांग्रेस उतरी विरोध के लिये विरोध के हथकण्डों पर

–**अम्बा चरण वशिष्ठ**........ 26

बिहार के विकास पुरुष की खुली पोल

–**विकास आनन्द**........ 28

अन्य

तमिलनाडु में प्रदेश भाजपा महासचिव रमेश की नृशंस हत्या घोर निन्दनीय 15

भाजयुमो सदस्यता अभियान प्रारंभ........ 17

भाजपा कार्यकारिणी बैठक, चण्डीगढ़........ 29

मुख पृष्ठ : *मध्य प्रदेश में जन-आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ*

ऐतिहासिक चित्र

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भोपाल बैठक में राजमाता विजयाराजे सिंधिया, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री सुन्दर लाल पटवा एवं अन्य नेतागण

प्रधानमंत्री का चुनाव

राजा नृप सिंह के प्रधानमंत्री वृद्ध हो गए थे। राजा ने प्रजा के बीच से किसी योग्य और व्यवहार कुशल व्यक्ति को यह पद देने का निर्णय किया। घोषणा करवा दी गई। प्रधानमंत्री बनने को इच्छुक अनेक लोग आए।

सभी उम्मीदवारों की छंटनी करने के बाद तीन को चुना गया। वे काफी पढ़े-लिखे विद्वान थे पर उनकी व्यवहार कुशलता की परीक्षा के लिए राजा ने उनसे कहा, 'तुम तीनों को अलग-अलग कमरों में बंद कर दिया जाएगा और बाहर से ताला लगा दिया जाएगा। तुम में से जो भी व्यक्ति आधे घंटे के अंदर ताला खोल कर बाहर आ जाएगा, उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा।'

यह सुनकर तीनों हैरत से एक-दूसरे को देखने लगे। उन्हें यह असंभव सी परीक्षा लगी। कुछ देर बाद उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। पहले कमरे में बंद व्यक्ति ने सोचा कि मात्र आधे घंटे में बाहर से बंद ताले को खोलना असंभव है। वह चुपचाप वहां रखे बिस्तर पर लेट गया। दूसरे कमरे में बंद व्यक्ति इधर-उधर घूमता रहा और सोचता रहा कि किस तरह बाहर के ताले को अंदर से खोला जा सकता है। लेकिन उसे भी कुछ नजर नहीं आया। तभी तीसरे कमरे का दरवाजा खुला और बाहर खड़े दूतों ने आवाज लगाई -'नए प्रधानमंत्री की जय हो।'

दोनों कमरों में बंद व्यक्ति बेचैनी से सोचते रहे कि तीसरे व्यक्ति ने दरवाजा कैसे खोला? इसके बाद दोनों उम्मीदवारों को राजा के सामने बुलाया गया। राजा ने कहा, 'तीसरे उम्मीदवार ने परीक्षा में सफलता पाई है। प्रधानमंत्री को शिक्षित होने के साथ-साथ व्यवहार कुशल होना भी जरूरी है। वास्तव में कमरों में ताला लगाया ही नहीं गया था। केवल तीसरे को छोड़कर आपने इसे खोलने का प्रयास ही नहीं किया। जबकि तीसरे ने इस पर विचार किया कि जब सवाल दिया गया है तो निश्चित समय में ही उसका हल भी आसपास होगा। इसलिए वह विजयी रहा।' दोनों उम्मीदवार लज्जित हो गए।

संकलन: रेनू सैनी

(नवभारत टा. से साभार)

व्यंग्य चित्र

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

देश चाहता है यूपीए से निजात

देश समझ नहीं पा रहा कि देश में क्या हो रहा है? सरकार केन्द्र में है या नहीं; यह भी देशवासियों को नहीं लग रहा। देश ने देश का ऐसा दौर कभी नहीं देखा। जो सत्ता में है वह कांग्रेस-नीत यूपीए इस जुगाड़ में है कि वह आगे सत्ता में कैसे आए! वहीं जो विपक्ष में भाजपा नीत एनडीए है वह तो अपने विपक्षी दायित्व के कारण सत्ता में आने की तैयारी में जुटे हैं। यूपीए ने देश का राजनैतिक वातावरण हताशा और निराशा भरा कर दिया है। अस्थिरता का ऐसा भयावह दृश्य भारत ने कभी नहीं देखा। कोई किसी के नियंत्रण में नहीं है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के साथ-साथ खबरपालिका एक-दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं। गत पांच वर्षों में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार को सर्वोच्च और उच्च न्यायालय ने जितनी फटकार लगाई है, इसके पूर्व भारत की किसी सरकार को न्यायालय की इतनी मार कभी नहीं पड़ी। केन्द्र की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने पूरे देश में अराजकता का वातावरण बना दिया है। देश की सबसे बड़ी पंचायत की मर्यादा दांव पर लग चुकी है। बहस से कतराती कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही है।

स्थिति का आंकलन तो इसी से किया जा सकता है कि ''बसपा और सपा'' की धमकियों के इशारे पर कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की कुर्सी टिकी हुई है। आखिर कैसे चलेगा देश! उजड़ी सरकार कांग्रेस नीत यूपीए भी बसपा-सपा को धमकाने के साथ-साथ सीबीआई के साथ ही एनआईए का भी दुरुपयोग कर इन दलों को नियंत्रण करने में लगी रहती है।

देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ऐसे दो दलों के हाथ चला गया है जो कुर्सी (सत्ता) के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अनुभवहीन अखिलेश सिंह पूरे उत्तर प्रदेश की प्रकृति को नहीं समझ पाए। बहिन मायावती येन-केन प्रकारेण देश को उत्तर प्रदेश बनाने में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की पहली आवश्यकता है कि उसे सपा-बसपा के हाथों से निकाला जाए। इस महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरे कार्य को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाजपा को इस दिशा में प्राथमिकता के साथ पहल करनी चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं कि बिहार में तो जद(यू) का नशा जनता उतार देगी। पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा को विशेष ध्यान देना होगा।

देश तो यूपीए से निजात चाहता है। हालात ही ऐसे हो गए है। कांग्रेस-नीत यूपीए के काबू में न देश है न देश की व्यवस्था। कब कौन सी चीज/वस्तु के दाम बढ़ जाए कहा नहीं जा सकता। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आए दिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई की मार से दम तोड़ रही जनता की जिन्दगी आम तौर पर सुरक्षित नहीं है। ''गरीबी'' कि स्थिति इतनी बदतर है कि गरीबों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कुछ लोगों के विकास से देश विकसित नहीं होता। देश का विकास समग्रता में होना चाहिए। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार में बैठे लोगों को ही यह लग रहा है कि वे यूपीए सरकार में क्यों हैं?

प्रतिक्रिया शून्य होते इस देश को कौन देखेगा? हम किसी मोर्चे पर सुरक्षित नहीं है। मसला देश की आंतरिक स्थिति का हो या फिर बाह्य स्थिति का। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। जिन हाथों में देश की कमान है, न वे सक्षम हैं और न ही समझदार। वर्तमान में तो ऐसा लग रहा है कि यह देश नहीं बल्कि कांग्रेस-नीत यूपीए ''भारत नाम की एक लोकतांत्रिक कंपनी'' चला रहे हैं, जिसका स्वरूप कारपोरेट जैसा बना दिया है। सूत्र कहीं हैं और सूत्रधार कोई और है। आखिर यह तमाशा कब तक चलेगा। कहीं न कहीं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में पनपा इस

देश की मजबूती का आधार है सुशासन : राजनाथ सिंह

भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने एडीसन सिटी, न्यू जर्सी में भाजपा के विदेशी मित्रों के एक विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए इस बात का खंडन किया कि ''भारत की सफलता की कहानी'' खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, हालांकि भारत के वर्तमान आर्थिक हालातों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सराहना नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूती लिए हुए है, जिसमें नीतियों को उचित तरीके से लागू करके और सुशासन के जरिए नई जान डाली जा सकती है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ''अगर अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में आई तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित शक्ति को सामने लाकर रख देंगे, जिसकी झलक भारत की जनता ने श्री अटलजी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान देखी थी।'' अपनी बात पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्होंने एनडीए सरकार और भारत में भाजपा शासित वर्तमान राज्य सरकारों द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।

अमरीका में भाजपा के विदेशी मित्रों के विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब भारत का समय आ चुका है और इस सपने को पूरा करने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपने-अपने देशों और अपनी क्षमताओं के साथ आगे आना चाहिए।

श्री नरेन्द्र मोदी को वीजा देने से इंकार करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, '' यह विरोधाभासी है कि एक तरफ तो अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में उनके सुशासन की प्रशंसा की जाती है और दूसरी तरफ वे उन्हें यात्रा वीजा देने से इंकार करते हैं। अमरीकी सरकार को अपने फैसले पर नये सिरे से और दोबारा विचार करना चाहिए।''

भारत-अमरीका संबंधों के मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने ही दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग की आधारशीला रखी और उम्मीद है कि भविष्य में इन संबंधों में और मजबूती आएगी।

बैठक को भाजपा महासचिव और विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री अनन्त कुमार ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, ''भाजपा 2014 के आगामी चुनाव के लिए अब रणभूमि में है। बैठक को पार्टी के प्रवक्ता और श्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार

डॉ0 सुधांशु त्रिवेदी और ओएफबीजेपी के संयोजक श्री विजय जौली ने भी संबोधित किया।

बैठक में ओएफबीजेपी के पूर्व प्रभारियों श्री केदारनाथ साहनी, श्री बाल आपटे और ओएफबीजेपी अमरीका के संस्थापक अध्यक्ष डॉ0 मुकुन्द मोदी तथा उत्तराखंड में पिछले दिनों आपदा में मारे गए लोगों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ■

अराजकता का तमाशा जनता को बंद करना चाहिए। इसके लिए जनता को स्वयं आगे आना होगा। जनधर्म का तकाजा है कि जनतंत्र को लुटने से बचाने के लिए जनता आगे आए। आपात्काल के बाद सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका जनता की थी। आज भी कमोबेश वही स्थिति है। कोई आगे आए न आए पर जनता को तो आना ही होगा। देश बचाना है तो अब कांग्रेस नीत यूपीए बसपा और सपा के विरूद्ध जनता को जनता के बीच जाकर बताना होगा कि ये देश के पोषक नहीं शोषक हैं। हम सभी जानते हैं कि जब जनता खड़ी हो जाएगी तो न केवल सत्ता परिवर्तन होगा, बल्कि जनतंत्र की रक्षा भी होगी। आज की महती आवश्यकता है कि प्रतिक्रिया शून्य स्थिति में जनता क्रिया प्रारम्भ करे। ■

समाज का कल्याण राज्य सरकार की दिवस की चिंता – रात्रि का स्वप्न : शिवराज सिंह चौहान

भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ स्वस्तिवाचन के साथ सामाजिक न्याय परिसर, उज्जैन में महाकाल की पूजा अर्चना के साथ 22 जुलाई को हुआ। वरिष्ठ भाजपा नेता सुंदरलाल पटवा, सुमित्रा महाजन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह तोमर, माखन सिंह तथा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिवराजसिंह चौहान को तिलक लगाकर आशीर्वाद यात्रा की सफलता की कामना करते हुए प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने भी जनआशीर्वाद यात्रा की सफलता की कामना की। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा को पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जनआशीर्वाद यात्रा के अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर खेत को पानी, हर घर को 24 घंटे बिजली, बेरोजगार को काम, युवा और छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं और समुचित अवसर प्रदेश में कृषि और उद्योगों में संतुलन लाना मध्यप्रदेश सरकार की दिवस की चिंता और रात्रि का स्वप्न है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में हुए विकास के लिए कांग्रेस के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र सरकार राज्य को सभी क्षेत्रों में सम्मानित करते हुए विकास के मामले में देश का अव्वल राज्य बता चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी विफलताओं पर लज्जित होने के बजाए भाजपा सरकार पर मिथ्या आरोप लगाकर जनभ्रम पैदा कर रही है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि 2003 की तुलना में मध्यप्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। मध्यप्रदेश की प्रगति देश में बेजोड़ है। विकास दर दहाई में देश में सबसे अधिक है। कृषि दर 18.91 गत वर्ष दर्ज हुई थी। इसमें इस वर्ष 13 प्रतिशत विकास दर ने इजाफा किया है। कांग्रेस के चरित्रहनन के आरोपों का पार्टी के कार्यकर्ता मुंहतोड़ जवाब देंगे।

शिवराजसिंह चौहान ने विकास के मापदंडों में भाजपा सरकार की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि हमने प्रदेश में बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट से बढ़ाकर 10600 मेगावाट किया है और आने वाले वर्ष में यह 14000 मेगावाट होगा। हर खेत को पानी देने के लिए सिंचाई सुविधाएं साढे लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 लाख हेक्टेयर की गयी है। कांग्रेस सरकारें मालवा को रेगिस्तान में बदलने जा रही थी, लेकिन भाजपा सरकार ने नर्मदा, क्षिप्रा लिंक परियोजना को धरातल पर उतारा है। नर्मदा को आने वाले दिनों में गंभीर, कालीसिंध, पार्वती नदियों से जोड़कर मालवा और निमाड़ को नए हरियाणा, पंजाब के रूप में सरसब्ज किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मन में

किसान के प्रति तड़प ने हमें जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल कर्ज देने की प्रेरणा दी। नतीजा सामने है। प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 49 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 127 लाख मीट्रिक टन हो गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद प्रदेश में मात्र 44 हजार किलोमीटर सड़कें थी।

भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनकी लंबाई 90 हजार कि.मी. 9 वर्षो में की है। बिजली का उत्पादन बढने से अब प्रदेश में जनरेटर और इन्वेटर इतिहास की चीजें रह गयी है। प्रदेश का बजट 33 हजार करोड़ रू. से बढ़ाकर 102000 करोड़ रू. किया गया है, यह मध्यप्रदेश में विकास की मोटी तस्वीर है और कांग्रेस के मिथ्या प्रचार की पोल खोलती है। शिवराजसिंह चौहान ने कांग्रेस को गरीब, कर्मचारी, युवा, किसान विरोधी बताते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश में दैनिक वेतन भोगियों के परिवारों को चूल्हे बूझा दिए थे। भाजपा सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिए है। शिक्षा के समान कार्य के लिए अगले 4 वर्षो में समान वेतन देने की योजना है। विकास और कल्याण के मामले में मध्यप्रदेश सरकार देश में बेजोड़ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मानते थे कि सरकार चलाना उनका एकाधिकार है, लेकिन भाजपा ने उनके झूठ की कलई खोल दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर मध्यप्रदेश तक कांग्रेस को परेशानी है कि शिवराजसिंह के रहते कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए शिवराजसिंह चौहान पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर उनकी छवि को खंडित किया जाए लेकिन प्रदेश की जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुझे पूरा भरोसा है कि वे कांग्रेस के छद्म को जनता की अदालत में बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पर कोई दाग लगाने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस छद्म विधानसभा आयोजित करके सड़को पर तमाशा करके लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं का मजाक उड़ा रही है जिसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। उन्होंने कोल ब्लाक के मामले में भी कांग्रेस के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि कांग्रेस स्वयं घोटाला का पर्याय रही है। जनता मध्यप्रदेश सरकार की उपलब्धियों जनता के कल्याण पर हमें आशीर्वाद देगी और जनआशीर्वाद ही तीसरी बार प्रदेश में सरकार के गठन के रूप में फलित होगा। कार्यकर्ताओं और जनता ने शिवराजसिंह चौहान के उद्बोधन पर बार बार तालियां बजाकर प्रोत्साहन दिया।

सरकार के दामन पर कोई दाग नहीं, - नरेन्द्रसिंह तोमर

जनआशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद नरेन्द्रसिंह तोमर ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के अभियान की सफलता की कामना करते हुए कहा कि आज का आयोजन पार्टी की योजना के अनुसार चुनाव अभियान का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसी परिसर में 2008 में शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में जनादेश अभियान के लिए महाकाल से आशीर्वाद लेकर जनता के बीच में गए थे और जनता ने प्रदेश में दूसरी बार भाजपा की सरकार का गठन करके मिथक को तोड़ा था। जनआशीर्वाद यात्रा की सफलता की कामना के साथ यात्रा आरंभ हो रही है। प्रदेश की जनता ने शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है कि उनकी संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि प्रदेश का चेहरा बदला है। किसानी की तस्वीर बदली है। गांव में खुशहाली आयी है। किसान संपन्न हुआ है। प्रदेश में रोजागर के अवसर बढ़े हैं। औद्योगिकरण की मुहिम बड़े शहरों से होते हुए नगरों और कस्बायी क्षेत्रों तक पहुंची है। मध्यप्रदेश में हो रही प्रगति की सराहना केन्द्र सरकार और पार्टी के बडे से बडे आलोचक भी करते है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता और पार्टी के जनाधार का कारण पार्टी की विचारधारा और जनता के प्रति संवेदनशीलता है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि वे विकास के मामले में

कभी भी और कही भी बहस करने के लिए तैयार है। भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस जिस तरह जगह जगह प्रहसन और तमाशें कर रही है उससे सिर्फ उसे अखबारों में सुर्खियां मिल सकती है जनता तो कांग्रेस को हास्य का पात्र समझ रही है।

नरेन्द्रसिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस अस्ताचल की ओर जा रही है। कांग्रेस कुंठाग्रस्त होकर जो आरोप लगा रही है उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास और जनकल्याण के रूप में अपनी पहचान बनायी है। कांग्रेस जहां घोटाला और भ्रष्टाचार का पर्याय है, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार सुशासन शुचिता और विकास के लिए पहचानी जाती है। इसका प्रमाण भाजपा शासित राज्यों में सभी को देखने को मिल रहा है। नरेन्द्रसिंह तोमर ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आव्हान किया कि वे मिशन 2013 की सफलता के लिए एकजुटता के साथ मैदान में उतरे और नवंबर 2013 के चुनाव की चुनौती से डंटकर निपटे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की निरंतर घट रही विश्वसनीयता और बढ़ती महंगाई, बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस हड़बड़ाहट में है और वह कोई भी कदम उठा सकती है। उन्होंने जनआशीर्वाद यात्रा की सफलता की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि वर्ष 2003, 2008 की तरह 2013 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का हृदय से समर्थन कर मध्यप्रदेश को देश का विकसित और उन्नत राज्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार के गठन के लिए सहयोग देगी।

पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने शिवराजसिंह चौहान को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यात्रा

जनआशीर्वाद यात्रा की झलकियां

- भारतीय जनता पार्टी की जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान उज्जैन में सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर जनता का सैलाब उमडा रहा।
- सभा के दौरान 20 हजार से अधिक लोग पंडाल के अंदर एवं 5 हजार से अधिक पंडाल के बाहर मौजूद थे।
- सभा के दौरान बुजुर्ग महिला मंच स्थल की तरफ आने की कोशिश कर रही थी तभी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने मातृशक्ति को प्रमाण कर उन्हें सहारा दिया उनसे कुछ समय बात कर उन्हें मंच पर बैठाया।
- मुख्यमंत्री जब सभा स्थल की ओर से यात्रा पर जा रहे थे तब शहर की जिन गलियों से रथ गमन हो रहा था तब घरों से महिलाएं एवं पुरूषों ने पुष्पवर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
- भारी बारिश के बावजूद लोगों ने जगह जगह खड़े होकर पुष्पवर्षा किया।
- शहर के प्रत्येक चौराहे पर युवाओं ने भगवा वस्त्र पहनकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
- रथ यात्रा के दौरान भारी संख्या में दो पहिया वाहन जनसमर्थन के लिए रथ के पीछे चल रहे थे।
- रथ यात्रा के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने भारी संख्या में सडको पर उपस्थित होकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

निश्चित रूप से सफल और समृद्धशाली होगी और स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जो काम किए है वह अदभुत है, इन्होंने सभी को पीछे छोड़ते हुए मध्यप्रदेश को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। 2013 में हम सरकार बनायेंगे और 2018 में भी। मध्यप्रदेश में कांग्रेस का अता पता नहीं है। कांग्रेस आज प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रही है।

पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद प्रभात झा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की यह यात्रा आध्यामिक एवं राजनैतिक साधना है। इस यात्रा के माध्यम से 8 हजार कि. मी. में प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे। जन जन का आशीर्वाद नवंबर में कमल खिलायेगा और सरकार बनायेगा। उन्होंने कहा कि आज हर युवा नारा लगा रहा है आंधी नहीं तूफान है, शिवराजसिंह चौहान है। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के पीछे कांग्रेस के महाराजा, इलाकेदार, जमींदार लग गए है उन्हें आश्चर्य है कि एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री कैसा बना ? उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो रही है और अपार जनसमर्थन से यात्रा की सफलता तय हो गयी है। 2013 में मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।

पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थावरचन्द गेहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, अटलबिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की इच्छा को प्रदेश में जनभावना को प्रखर करने का काम कर रहे है। जनआशीर्वाद यात्रा के लिए

उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को महाकाल ने आशीर्वाद दिया है। जनता ने जनसमर्थन दिया है। जिससे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनायेंगे।

चुनाव प्रबंधन प्रभारी अनिल माधव दवे ने जनआशीर्वाद यात्रा के प्राणगीत के संबंध में बताते हुए कहा कि इस यात्रा के गीत से स्पंदन पैदा होगा, वह पूरे प्रदेश में मतदान केन्द्र तक जायेगा और हर बूथ स्तर तक कमल खिलेगा।

यात्रा गीत के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह तोमर एवं उपस्थित अतिथिगणों ने सुशासन और कुशासन, घोटालों की पाठशाला और जैत गांव से मुख्यमंत्री तक का सफर की पुस्तकों का विमोचन किया। उज्जैन जिला अध्यक्ष इकबाल गांधी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्याम बंसल ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान एवं नरेन्द्रसिंह तोमर सहित अतिथिगणों का शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित किया।

वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा ने कहा कि महाकाल की नगरी और श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जनआशीर्वाद यात्रा की शुरूआत की है, उसे जनता के समर्थन से सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में कावड़ यात्री नर्मदा का जल महाकाल को अर्पण करते है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने पूरी नर्मदा ही उज्जैन लाकर महाकाल को अर्पित की है। जिससे हर वर्ष नर्मदा के जल से महाकाल का अभिषेक होगा। महाकाल के आशीर्वाद से पिछले बार जितनी सीटें जीती थीं उससे भी अधिक सीटें इस बार मिलेगी।

स्वागत भाषण देते हुए वरिष्ठ नेता डॉ. सत्यनारायण जटिया ने कहा कि यह अभिनव आगाज 2003 में शुरू हुआ था। पार्टी के पहले कदम पर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया। दूसरी बार भी अपार जनसमर्थन से नवाजा और तीसरी बार स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने के लिए आपका समर्थन और आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आपके द्वार पहुंच रहे है। गुरूपूर्णिमा के अवसर पर यह यात्रा प्रारंभ होकर प्रदेश भर में पहुंचेगी।

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद फग्गनसिंह कुलस्ते ने कहा कि महाकाल भगवान से संकल्प लेकर यह यात्रा सफलता के सौपान को प्राप्त करेगी। यात्रा की सफलता के लिए वनवासी क्षेत्रों की ओर से मैं मंगल कामना करता हूं।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद कैलाश जोशी, प्रदेश संगठन मंत्री अरविन्द मेनन, वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद सुमित्रा महाजन, मंत्री अर्चना चिटनीस, लक्ष्मीकांत शर्मा, जगदीश देवड़ा, उमाशंकर गुप्ता, अजय विश्नोई, रंजना बघेल, के.एल. अग्रवाल, पारस जैन, गौरीशंकर बिसेन, हरिशंकर खटीक, राष्ट्रीय सचिव डॉ. सुधा मलैया, प्रदेश महामंत्री व सांसद माया सिंह, यात्रा प्रभारी नंदकुमारसिंह चौहान, विनोद गोटिया, कृष्णमुरारी मोघे, रामपाल सिंह, तपन भौमिक, महापौर रामेश्वर अखण्ड, उषा चतुर्वेदी, उषा ठाकुर, अंजू माखीजा, अनुसुईया उइके, साधना सिंह चौहान, तनवीर अहमद, बाबूलाल जैन, मदनमोहन गुप्त, अजय प्रताप सिंह, चेतन्य काश्यप, रामेश्वर शर्मा, विजेश लुणावत, डॉ. हितेष वाजपेयी, संजय कुमार खोचे, गोविन्द मालू, अमरदीप मौर्य, मोहन यादव, प्रदीप पाण्डे, सन्नवर पटेल, हिदायतुल्ला शेख, नंदकिशोर पाटीदार, चन्द्रकांत गुप्ता, शैलेन्द्र शर्मा, सुरेन्द्र पटवा, मोर्चा के समस्त अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश शासन के मंत्रीगण एवं संभाग व जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में जनसमूह उपस्थित था। यात्रा मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं धार्मिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का जगह जगह स्वागत किया गया। जनता ने पुष्पवर्षा एवं फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। यह यात्रा उज्जैन नगर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मार्गो से होते हुए घटिया, तराना, माकडोन, घोसला, महीदपुर, खाचरोद होते हुए नागदा रात्रि विश्राम करेगी। यात्रा मार्ग में शिवराजसिंह चौहान ने जनआशीर्वाद यात्रा रथ के माध्यम से जगह जगह जनसमूह को संबोधित किया। ■

उत्तराखंड आपदा राहत समिति घोषित

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में सुझाव संकलित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति आपदा प्रभावित लोगों को प्रभावी रूप से राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के बारे में सुझाव संकलित करेगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित है :

सुश्री उमा भारती : संयोजक
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष)

श्री भगत सिंह कोशियारी : सदस्य
(संसद सदस्य)

सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सदस्य
(संसद सदस्य)

■

ओसामा बिन लादेन सम्बन्धी पाकिस्तान का न्यायिक आयोग

✍ लालकृष्ण आडवाणी

वह मई, 2011 की शुरुआत थी जब सील टीम सिक्स (SEAL TEAM SIX) के रेड स्क्वाड्रन के चुनिंदा 24 जवानों ने पाकिस्तान के एबटावाद स्थित ठिकाने पर धावा बोला था जहां अनेक वर्षों से ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था।

उपरोक्त घटना को, पाकिस्तान में सन् 1971, जब न केवल पाकिस्तान को प्रमुख युद्ध में औपचारिक रुप से पराजय झेलनी पड़ी अपितु पाकिस्तान के विघटन से एक नए स्वतंत्र देश-बंगलादेश का भी जन्म हुआ था-के बाद सर्वाधिक बुरे राष्ट्रीय अपमान के रुप में वर्णित किया गया।

Laden अमेरिकी सैनिकों द्वारा ओबामा को मारे जाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति जावेद इकबाल की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय जांच आयोग गठित किया। अन्य तीन सदस्यों में अशरफ जहांगीर काजी भी शामिल थे जो कुछ वर्ष पूर्व नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त थे।

आयोग ने 336 पृष्ठों वाली अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 4 जनवरी, 2013 को सौंपी। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट को 'गुप्त' करार दे दिया। लेकिन 8 जुलाई को अंग्रेजी टेलीविजन अल जजीरा ने किसी प्रकार इस रिपोर्ट की एक प्रति हासिल कर प्रकाशित कर दिया। स्पष्टतया, अल जजीरा की रिपोर्ट के आधार पर दि न्यूयार्क टाइम्स, दि गार्डियन, और कुछ दूसरे पश्चिमी समाचार पत्रों ने भी रिपोर्ट का एक सारांश प्रकाशित किया। अपने ब्लॉग के नियमित पाठकों के लिए मैं दि न्यूयार्क टाइम्सकी रिपोर्ट यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। दि सन्डे गार्डियन की रेजिडेंट सम्पादक सीमा मुस्तफा द्वारा, स्टेटस्मैन (भारत) में इस रिपोर्ट को दो किश्तों में जुलाई 20 और 21 में प्रकाशित किया।

न्यूयार्क टाइम्स के लंदन स्थित डेक्लान वाल्स की यह रिपोर्ट निम्न है:

लंदन - सोमवार (8 जुलाई) को मीडिया को 'लीक' की गई एक हानिकारक पाकिस्तानी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक "सामूहिक अक्षमता और उपेक्षा" के चलते लगभग एक दशक तक ओसामा बिन लादेन निर्बाध रूप से पाकिस्तान में रहा। सर्वोच्च न्यायालय के एक जज की अध्यक्षता वाले चार सदस्यीय एबटाबाद कमीशन ने देश के शीर्ष गुप्तचर अधिकारियों सहित 201 लोगों से बातचीत की और 2 मई, 2011 को अमेरिकी धावे से जुड़ी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की है, जिसमें अलकायदा का सरगना बिन लादेन मारा गया और पाकिस्तानी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।

न्यूयार्क टाइम्स के लंदन स्थित डेक्लान वाल्स की यह रिपोर्ट निम्न है:

लंदन - सोमवार (8 जुलाई) को मीडिया को 'लीक' की गई एक हानिकारक पाकिस्तानी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक "सामूहिक अक्षमता और उपेक्षा" के चलते लगभग एक दशक तक ओसामा बिन लादेन निर्बाध रूप से पाकिस्तान में रहा।

सर्वोच्च न्यायालय के एक जज की अध्यक्षता वाले चार सदस्यीय एबटाबाद कमीशन ने देश के शीर्ष गुप्तचर अधिकारियों सहित 201 लोगों से बातचीत की और 2 मई, 2011 को अमेरिकी धावे से जुड़ी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की है, जिसमें अलकायदा का सरगना बिन लादेन मारा गया और पाकिस्तानी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।

हालांकि कमीशन की रिपोर्ट 6 मास पूर्व पूरी हो गई थी परन्तु पाकिस्तानी सरकार ने इसे दबा दिया था और पहली 'लीक' प्रति सोमवार को अल जजीरा

ने सार्वजनिक की।

इस प्रसारण संस्था ने 336 पृष्ठों की रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया, इसमें यह भी स्वीकारा गया कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी के मुखिया की गवाही वाला एक पृष्ठ इसमें नहीं है जिसमें प्रतीत होता है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के सुरक्षा सहयोग के तत्वों को समाहित किया गया है।

कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के टेलीकॉम रेग्यूलेटर ने पाकिस्तान के भीतर अल जजीरा की बेवसाइट को देखने से बचाने हेतु ठप्प कर दिया।

कुछ मामलों में कमीशन अपेक्षाओं के अनुरूप दिखा। अपनी रिपोर्ट में इसने अफगानिस्तान के टोरा बोरा में अमेरिकी हमले के बाद 2002 के मध्य में पाकिस्तान न आए बिन लादेन को पकड़ने में पाकिस्तान की असफलता के लिए षड्यंत्र के बजाय अक्षमता का सहारा लिया है।

लेकिन अन्य संदर्भों में रिपोर्ट आश्चर्यजनक रही। इसमें प्रमुख सरकारी अधिकारियों के भावात्मक संशयवाद सम्बन्धी झलक है, जो कुछ सुरक्षा अधिकारियों द्वारा चोरी-छिपे मदद करने की संभावनाओं की बात कहती है।

यह कहती है कि "कुछ स्तरों पर मिली भगत, सहयोग और संबंध को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है"।

रिपोर्ट, बिन लादेन जिसने अमेरिकी सैनिकों के हाथों में पड़ने से पूर्व सन् 2002-2011 के बीच 6 ठिकाने बदले थे, के दौर के उसके जीवन की ललचाने वाले नये खुलासे करती है। बताया जाता है कि अनेक बार अलकायदा के मुखिया ने अपनी दाढ़ी साफ करा रखी थी और पाकिस्तान या अमेरिकी सेना के हाथों में आने से बचने के लिए 'काऊ ब्याय हैट' भी पहनना जारी किया था।

एक बार उस वाहन को तेजी से चलाने के जुर्म में रोका गया था जिसमें वह बैठा था मगर पुलिस अधिकारी उसे पहचानने में असमर्थ रहे और उसे जाने दिया।

रिपोर्ट ने पाकिस्तानी अधिकारियों की खिंचाई की है कि उन्होंने देश में सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी के ऑपरेशन्स करना बंद कर दिए हैं और नाना प्रकार से अमेरिकी कार्रवाई को गैर कानूनी या अनैतिक ठहराया है। इसके अनुसार सी. आई.ए. ने प्रमुख सहायक एजेंसियों की कायदा के मुखिया की जासूसी के लिए उपयोग किया, 'किराए के ठगों' को साधा और पाकिस्तानी सरकार में अपने सहयोगियों को पूरी तरह से धोखा दिया।

रिपोर्ट कहती है: "अमेरिका ने एक आपराधिक ठग की तरह काम किया है।"

अपनी अनियंत्रित भाषा और संस्थागत दवाबों के चलते रिपोर्ट पाकिस्तान में बिन लादेन के इधर-उधर छुपने की अवधि का सर्वाधिक सम्पूर्ण अधिकारिक वर्णन और अमेरिकी नेवी सील के हमले जिसने उसकी जान ली, को प्रस्तुत करती है।

चार सदस्यीय कमीशन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जावेद इकबाल, एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, एक सेवानिवृत्त कूटनीतिक और एक सेवानिवृत्त सैन्य जनरल हैं। इसकी पहली बैठक अमेरिकी हमले के दो महीने बाद जुलाई, 2011 में हुई और इसकी 52 सुनवाई हुई तथा सात बार यह इलाके में गए।

अमेरिकी अधिकारियों ने कमीशन के साथ कोई सहयोग नहीं किया और सोमवार को विदेश विभाग के प्रवक्ता जेन पास्की ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। पाकिस्तान के घटनाक्रम पर नजर रखने वाले एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यद्यपि कमीशन की भारी भरकम रिपोर्ट पढ़ने को नहीं मिली है परन्तु उन्होंने कहा कि प्रकाशित सारांशों से प्रतीत होता है कि दस्तावेज बताते हैं कि "पाकिस्तानी कुछ तो जानते हैं कि कैसे बिन लादेन का वहां अंत हुआ।"

कई स्थानों पर पाकिस्तानी रिपोर्ट अमेरिकियों द्वारा लादेन को पकड़े जाने से पहले पाकिस्तानी अधिकारियों की असफलता पर कुपित होती और हताशा प्रकट करती है।

इसमें उन सीमा अधिकारियों की अकुशलता को रेखांकित किया गया है जिन्होंने उसकी एक पत्नी को ईरान जाने

शेष पृष्ठ 30 पर

Osama & Compound ***कमीशन रेखांकित करता है कि कैसे आई.एस.आई. अधिकांशतया नागरिक नियंत्रण से बाहर ही ऑपरेट करती है। बदले में जनरल पाशा उत्तर देते हैं कि सी.आई.ए. ने सन् 2001 के बाद बिन लादेन के बारे में सिर्फ असंबद्ध गुप्तचर सूचनाएं ही साझा की। रिपोर्ट में लिखा है कि एबटाबाद पर धावा करने से पूर्व अमेरिकियों ने बिन लादेन के चार शहरों-सरगोधा, लाहौर, सियालकोट और गिलगिट में होने की गलत सूचना दी।***

कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव का साम्प्रदायिकरण करने की कोशिश क्यों कर रही है

✍ अरुण जेटली

कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने ''इंडियन मुजाहिदीन'' की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व को अभूतपूर्व तरीके से तर्कसंगत ठहराया है। इंडियन मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है। इसे भारत में गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोधक) कानून के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन कहा गया है। यूपीए सरकार ने इस पर लागू प्रतिबंध जारी रखा है। अमरीकी विदेश विभाग ने इसे विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया है। ब्रिटेन ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। गंभीर राजनीतिक पर्यवेक्षकों को इस बात पर ताज्जुब है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भारत में इंडियन मुजाहिदीन की उत्पत्ति को अर्थात् 2002 के गुजरात दंगों की प्रतिक्रिया स्वरूप एक संगठन के रूप में इसके गठन को क्यों तर्कसंगत ठहरा रहे हैं।

शासन के संकट और नेतृत्व के अभाव का सामना करने के साथ यूपीए का मुख्य मुद्दों से भटकना उसकी हताशा प्रकट करता है। किसी भी सूरत में यूपीए को धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने-मरोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए यूपीए के पास अब एक ही विकल्प बचा है। देश की राजनीति का साम्प्रदायिकरण किया जाए और चुनाव का एजेंडा बदल दिया जाए। जो लोग यूपीए को सत्ता से उखाड फेंकना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें शासन के मुद्दों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जिनसे यूपीए बचने की कोशिश करेगी।पिछले कुछ सप्ताहों में यूपीए के नेताओं ने इस रणनीति को अपनाने का गंदा प्रयास किया।

यूपीए अपने अस्तित्व के दसवें साल में है। आम चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, यूपीए को सत्ता विरोधी माहौल से जूझना पड़ रहा है। नेतृत्व की विफलता किसी से छिपी नहीं है। नेतृत्व अक्षम दिखाई दे रहा है। शासन पूरी तरह अयोग्य साबित हुआ है। सरकार के पास इस बात की समझ नहीं रह गई है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए।

यूपीए ने भ्रष्टाचार को अपनी नीति का नया दिशासूचक सिद्धांत बनाया है। यूपीए का दस साल का कुशासन दिखाता है कि उसने किस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को तोड़ा-मरोड़ा है। यूपीए शासन के खराब शासन के बाद आगामी आम चुनाव की कार्यसूची में एक प्रभावशाली और स्वच्छ सरकार का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहेगा।

कांग्रेस की परंपरागत रणनीति रही है कि जब भी वह शासन के मामले में विफल रहती है, तो वह ब्रह्मास्त्र यानी पार्टी के पहले परिवार के कथित करिश्मे का इस्तेमाल करती है। दुर्भाग्यवश करिश्मा भी अब बेअसर दिखाई दे रहा है। यूपीए का निवर्तमान नेतृत्व कथित तौर पर निकम्मा है।

शासन के संकट और नेतृत्व के अभाव का सामना करने के साथ यूपीए का मुख्य मुद्दों से भटकना उसकी हताशा प्रकट करता है। किसी भी सूरत में यूपीए को धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने-मरोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

इसलिए यूपीए के पास अब एक ही विकल्प बचा है। देश की राजनीति का साम्प्रदायिकरण किया जाए और चुनाव का एजेंडा बदल दिया जाए। जो लोग यूपीए को सत्ता से उखाड फेंकना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें शासन के मुद्दों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जिनसे यूपीए बचने की कोशिश करेगी।पिछले कुछ सप्ताहों में यूपीए के नेताओं ने इस रणनीति को अपनाने का गंदा प्रयास किया। इसके तीन स्पष्ट संकेत हैं। पहला, यूपीए ने नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा। गुजरात में कांग्रेस की आरंभिक रणनीति मोदी पर जमकर हमले करने की रही है। मोदी राजनीतिक लड़ाई में हमेशा कांग्रेस से आगे निकल गए। इस रणनीति को प्रतिकूल पाकर कांग्रेस ने इसके बाद अपने प्रचार में वैकल्पिक नीति अपनाते हुए ऐसा दिखाया मानो उनके लिए मोदी का कोई अस्तित्व नहीं है। केन्द्र में कांग्रेस ने पहले चरण में मोदी पर लगातार कई हमले किए। इस प्रक्रिया में उन्हें लगा कि उनकी स्थिति अच्छी हो गई है। जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि उनकी रणनीति उल्टी पड़ गई और वह फिर से मोदी की अनदेखी करने का नाटक करने लगे।

दूसरा, केन्द्र सरकार ने इशरत जहां मामले में सीबीआई के जरिए जो रणनीति अपनाई उसने कई लोगों को परेशानी में

डाल दिया। सीबीआई ने इस मामले को दबाने और लश्कर-ए- तौयबा से संबंध की अनदेखी करने की रणनीति अपनाई तथा इस देश के समूचे सुरक्षा तंत्र को खोलकर रख दिया। इशरत जहां के एलईटी से कथित संबंधों के बारे में पहली चार्जशीट पर चुप्पी क्यों छाई रही? क्या गुप्तचर ब्यूरो ने इस हिस्से के बारे में कश्मीर में अपने सूत्रों से विस्तृत जानकारी ली थी? क्या भारत का सुरक्षा तंत्र और हमारी खुफिया एजेंसियों को एलईटी की बातचीत बीच में सुनने का हक नहीं है, जिन पर निगरानी रखी जानी चाहिए और उनसे पूछताछ की जानी चाहिए? क्या ये सभी कदम आतंकवाद पर काबू पाने के लिए थे या एक अपराध की साजिश करने के लिए थे? इस सवाल का जवाब इस बात में है कि क्या कथित शिकार व्यक्ति के एलईटी से संबंध थे या नहीं। सरकार के जांच हथियार के रूप में सीबीआई ने एलईटी से संबंध के बारे में चुप्पी साधना उचित समझा। डेविड हेडली की एनआईए पूछताछ में पैरा'-168 को किसने हटाया, जिसमें एलईटी मॉडयूल के बारे में इसका जिक्र किया गया था? क्या सीबीआई एलईटी के सक्रिय सदस्यों की रिकॉर्ड की गई आवाज उनके भारतीय संपर्कों को पहचानने से इनकार करने की हद तक जा सकती है? क्या सीबीआई ने कुछ पुलिस वालों के साथ सौदेबाजी की है, जो कथित रूप से मुठभेड़ में शामिल थे और जिन्होंने अपना चरित्र एक आरोपी से एक गवाह के रूप में बदल लिया, ताकि वे देश के सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था की साख मिटा दें? मुठभेड़ की सच्चाई की तह में जाए बिना मैंने ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं, जो इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि एलईटी के मॉडयूल को शहीद के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है और भारत की सुरक्षा तथा खुफिया व्यवस्था को खलनायक बनाया जा रहा है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की सोची-समझी रणनीति अपनाई जा रही है?

तीसरा, इस संदर्भ में इंडियन मुजाहिदीन के शकील अहमद के बयान का विश्लेषण किया जाना चाहिए। 9/11 के बाद दुनिया का ध्यान विभिन्न आतंकवादी गुटों की तरफ गया। पाकिस्तान पर आरोप लगा कि वह भारत में सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। एनडीए सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगाया। इस के बाद इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ। पाकिस्तान एक ऐसा संगठन बनाना चाहता था, जो भारतीय दिखाई दे और जिसका संचालन करने के लिए उसमें अनेक भारतीय हों। बम बनाने की तकनीक और इसके लिए धनराशि सीमा पार से आती है। इसमें इंडियन शब्द होने के कारण पाकिस्तान को यह मौका मिला गया कि हर बार आतंकवादी हमला होने पर वह हमले में हाथ होने से इनकार कर देता है। अपने अस्तित्व में आने के बाद से इंडियन मुजाहिदीन भारत में बड़ी संख्या में हमलों के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को इतिहास दोबारा लिखना चाहिए। उनका प्रयास इंडियन मुजाहिदीन की ऐसे व्यथित लोगों के संगठन के रूप में तस्वीर प्रस्तुत करना है, जिसमें गुजरात दंगों के पीड़ित शामिल हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ और इंडियन मुज़ाहिदीन के गठन के पीछे पाकिस्तान की रणनीति की अनदेखी की। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का साम्प्रदायिकरण करने का एक निराशाजनक प्रयास है। ■

(लेखक राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं)

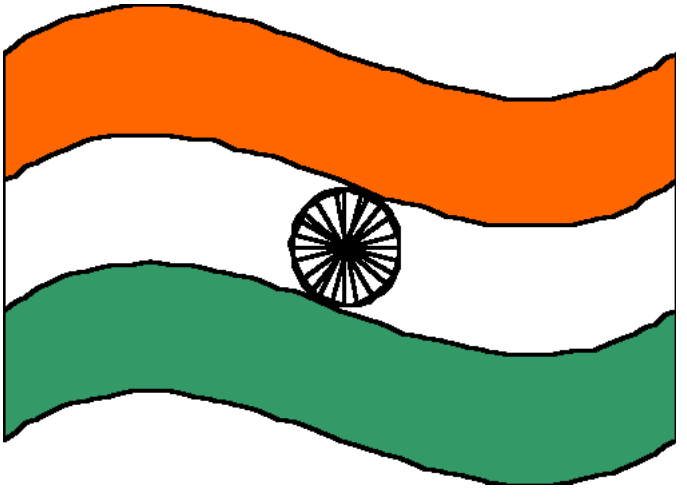

कमल संदेश के सुधी पाठकों को 67वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) की हार्दिक शुभकामनाएं!

प्रदेश भाजपा महासचिव वी. रमेश की नृशंस हत्या घोर निन्दनीय

गत 19 जुलाई 2013 को देर रात भाजपा तमिलनाडु के महासचिव श्री बी. रमेश की निर्मम प्रहार किया गया तथा तमिलनाडु के सेलम में उनके घर तथा कार्यालय के नजदीक हत्या कर दी गई। भाजपा इस हत्या की घोर निंदा करती है।

भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमन ने प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि श्री रमेश व्यवसाय से चार्टर्ड एकाउण्टेंट थे और अपने क्षेत्र में विख्यात और सम्माननीय नागरिक थे। उन्होंने पार्टी में विचारधारा के प्रति पूर्ण समर्थन तथा प्रतिबद्धता से अपनी जगह बना कर उन्नति की थी।

वे तमिलनाडु ईकाई के महासचिव तथा भाजपा कोर समिति के सदस्य थे। मृदुभाषी होने के साथ सौहाद्रपूर्ण स्वभाव रखते थे तथा वे एक शक्तिशाली वक्ता तथा लेखक भी थे। वे 1991 से भाजपा में सक्रिय थे।

रमेश जी की नृशंस हत्या तमिलनाडु में चल रही शृंखलाबद्ध हत्याओं में से एक थी, जिसमें एक वर्ष के अन्दर उस राज्य में उन्हें हत्या का निशाना बनाया गया। इससे पूर्व, भाजपा मेडिकल सेल के प्रदेश सचिव डॉ. अरविन्द रेड्डी की भी इसी प्रकार नृशंस हत्या हुई थी। इसी सिलसिले में भाजपा कार्यकर्ता तथा रामानाथपुरम जिले के परमकुडी के पूर्व कौंसिलर एवं नागापट्टीनाम जिले के भाजपा अध्यक्ष श्री युगाजेण्डी की भी हत्याएं हुई हैं।

भाजपा नेताओं पर बड़े योजनाबद्ध ढंग से हमला किया जा रहा है। सौभाग्य से, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री एम आर गांधी (नागर कॉयल) और श्री एच. राजा, प्रदेश अध्यक्ष (इलयानकुडी) बच कर जीवित रहे।

इसी प्रकार की हत्याओं/हमलों में अन्य संगठनों के लोग भी शिकार हुए हैं। एक महीने से कम समय में हिन्दु मुन्नानी के प्रदेश सचिव की भी हत्या हुई है।

श्री आनन्द, जिला सचिव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और श्री मंजुनाथ, हिन्दु मुन्नानी, जिला नीलगिरी पर बुरी तरह से हमला हुआ। एक वर्ष से भी अधिक बीते, श्री भास्कर, प्रचारक, जिला डिण्डुकल (आरएसएस) पर भी हमला हुआ था।

यह स्मरण रखना आवश्यक है कि 2011 में भ्रष्टाचार तथा कालेधन के विरूद्ध निकाली गई रथयात्रा में भी मदुरई के निकट आलमपट्टी में पाइप बम से श्री लालकृष्ण आडवाणी पर भी हमला करने की योजना बनाई गई थी, परंतु सौभाग्य से तमिलनाडु पुलिस ने समय पर इस षड्यंत्र का पता लगा लिया था। किन्तु, आज भी जैसा हमें पता है कि इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिनमें से कम से कम दो लोग तो अभी तक फरार हैं।

भाजपा घोषित करती है कि हम अपने हर कार्यकर्ता के समर्थन में उसके साथ खड़े रहेंगे और इन समाज-विरोधी तत्वों को कुचल कर रख देंगे। राजनैतिक हमलों और हत्याओं के खतरनाक प्रवृत्तियों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार को इन प्रत्येक हमलों को जांच कराने के लिए उच्च स्तरीय विशेष जांच की व्यवस्था करनी चाहिए जो लोग खतरे में पड़े हैं, उनकी तुरंत रक्षा की जानी चाहिए।

जांच समिति गठित

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने भाजपा तमिलनाडु राज्य इकाई के महासचिव वी रमेश की हत्या की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। राज्य सभा सदस्य व पार्टी प्रवक्ता श्री प्रकाश जावड़ेकर इस समिति के संयोजक होंगे। पार्टी की प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमण और कर्नाटक से भाजपा के सांसद श्री अनंत हेगड़े इसमें बतौर सदस्य शामल होंगे। समिति को शीघ्र ही इस मामले से जुड़े तथ्य व रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपने को कहा गया है।

तमिलनाडु में इससे पहले भाजपा के एक अन्य नेता वी अरविंद की हत्या की जा चुकी है। इसके अलावा कई अन्य नेताओं को निशाना बनाया है। ■

भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव अभियान समिति घोषित

वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में व गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय चुनाव अभियान समिति निम्न रहेगी:-

1. श्री (डॉ.) मुरली मनोहर जोशी
2. श्री वेंकैया नायडू
3. श्री नितिन गडकरी
4. श्रीमती सुषमा स्वराज
5. श्री अरुण जेटली
6. श्री अनंत कुमार
7. श्री थावरचंद गहलोत
8. श्री रामलाल
9. श्री शिवराज सिंह चौहान
10. श्री (डॉ.) रमन सिंह
11. श्री मनोहर परिकर

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह तथा केन्द्रीय चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चुनाव अभियान की दृष्टि से विभिन्न समितियाँ व उनके नाम घोषित किये हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

1. घोषणा पत्र :

अध्यक्ष - डॉ मुरली मनोहर जोशी

सदस्य - श्री जसवंत सिंह, श्री यशवंत सिन्हा, श्री प्रेम कुमार धूमल, श्री सुशील कुमार मोदी, श्री जुएल उराव, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, प्रो. लक्ष्मीकान्ता चावला, श्री सत्यपाल मलिक, श्री बंडारु दत्तात्रेय, श्रीमती विजया चक्रवर्ती, श्री सत्यनारायण जटिया, श्री शाहनवाज हुसैन, श्री महेश चन्द्र शर्मा, श्री कंचन गुप्ता, श्री षणमुखनाथन।

2. विज़न डॉक्यूमेंट :

श्री नितिन गडकरी

श्री ओम प्रकाश कोहली, श्री राजेश शाह, श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रो. हरी बाबू।

3. प्रचार एवं प्रसिद्धि समिति :

श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली :

श्री अमित शाह, डॉ. सुधांशु त्रिवेदी।

4. रैलियाँ :

श्री अनंत कुमार, श्री वरुण गाँधी।

5. संसदीय सम्मेलन :

श्री थावरचंद गेहलोत, श्री जे.पी. नड्डा, श्री पुरुषोत्तम रुपाला

श्री विनोद पांडे, श्री एल. गणेशन।

6. वर्गवार सम्मेलन :

श्री मुरलीधर राव, श्री विनय कटियार

श्री श्याम जाजू, श्री कृष्ण दास, श्रीमती लुईस मरांडी, श्री विजय सोनकर शास्त्री, श्री महेन्द्र पाण्डेय।

(सभी मोर्चो व प्रकोष्ठों के संयोजकों का सहयोग रहेगा।)

7. नव-मतदाता अभियान :

श्री अमित शाह, श्री नवजोत सिंह सिद्धू

श्री त्रिवेन्द्र रावत, श्रीमती पूनम महाजन।

8. पारंपरिक अभियान :

श्रीमती स्मृति ईरानी, कै. अभिमन्यू, सुश्री वाणी त्रिपाठी।

9. बुद्धिजीवी सम्मेलन Friends of BJP :

श्री राजीव प्रताप रुडी, श्री प्रकाश जावेडकर, डॉ. तमिल ईसाई

10. विशेष संपर्क अभियान :

श्री नितिन गडकरी, सुश्री उमा भारती, डॉ. सी.पी. ठाकुर, डॉ. जे.के जैन, श्रीमती मृदला सिन्हा, श्री कलराज मिश्र, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

11. चुनावी संगठन :

श्री रामलाल

श्री वी. सतीश, श्री सौदान सिंह।

12. कांग्रेस यूपीए के खिलाफ आरोप पत्र :

श्री गोपीनाथ मुंडे, श्री रविशंकर प्रसाद, श्रीमती आरती मेहरा, श्री किरीट सोमैया, श्रीमती निर्मला सीतारमन, श्रीमती मिनाक्षी लेखी।

13. Information Communication Campaign :

श्री पीयूष गोयल

IT & Communication Cell का सहयोग रहेगा।

14. जन समीक्षा और जन भागीधारी :

श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री रामेश्वर चौरसिया :
श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री नलिन कोहली।

15. साहित्य निर्माण :

श्री बलबीर पुंज, श्री प्रभात झा
श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, श्रीमती सुधा मलैया।

16. कार्यक्रम और यातायात :

श्री मुख्तार अब्बास नकवी
डॉ. अनिल जैन, श्री अरुण सिंह।

17. उत्तर-पूर्व अभियान :

श्री एस.एस. अहलूवालिया, श्री तापिर गांव
श्री पद्मनाभ आचार्य, श्री किरन रिज्जू।

18. चुनाव आयोग और कानून संबंधी :

श्री सतपाल जैन, श्री भूपेन्द्र यादव,
श्री रामकृष्ण, श्रीमती पिंकी आनंद।

19. बूथ समिति संकलन :

श्री राजीव प्रताप रुडी, श्री अनिल माधव दवे, श्रीमती सुधा यादव,
श्रीमती रेणु कुशवाहा।

20. विशेष :

- रैलियाँ, संसदीय सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन व Friends of BJP विभागों का मार्गदर्शन श्री वेंकैया नायडू करेंगे।
- विज़न डॉक्यूमेंट व विशेष सम्पर्क के साथ वर्गवार सम्मेलन व नव-मतदाता अभियान का मार्गदर्शन श्री नितिन गडकरी करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा श्री नितिन गडकरी को दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर विशेष ध्यान देने के लिए नियुक्त किया है। श्री नवजोत सिंह सिद्धू उनका सहयोग करेंगे।

भाजयुमो

'जुड़ेगा युवा-बदलेगा भारत' नारे के साथ सदस्यता अभियान शुरू

आज सर्वविदित है कि विश्व का सर्वाधिक युवा भारत में रहते हैं जिसकी 65 फीसदी आबादी युवा है। युवा मोर्चा समय-समय पर सदस्यता अभियान चलाता रहता है। इस बार के सदस्यता अभियान में एक करोड़ युवा सदस्यों को जोड़ना का लक्ष्य रखा गया है। ये अभियान दो चरणों को होगा। प्रथम चरण 15 जुलाई से शुरू हो चुका है।

सबसे अधिक सदस्यता करने वाले पहले 500 युवाओं को और सोशल मीडिया के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव के सम्बंधित सबसे बेहतरीन सुझाव देने वाले 20 युवाओं को भाजपा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर दिया जायेगा।

आज का युवा सूचना तकनीकी का भरपूर उपयोग कर रहा है। इसलिए युवा मोर्चा भी अपने इस अभियान में सोशल मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट, टेलिफोन नं. एवं मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का काम करेगा। घर-घर जाकर सदस्य बनाने के साथ ही आनलाईन सदस्य भी बनाया जाएगा। इस माध्यम से जुड़ने वाले युवाओं को 'युवा मित्र' कहा जायेगा। 23 जुलाई से इस अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। जिसमें परंपरागत तरीके से यानी घर-घर जाकर सदस्य बनाने का कार्य महान क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद के जन्म दिन से किया जाएगा।

विशेष रूप से इस अभियान में 18 से 35 वर्ष आयु के नवमतदाता, ग्रामीण युवा, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग और ख्याति प्राप्त युवाओं एवं युवतियों को जोड़ना प्राथमिकता होगी। 2014 के चुनाव में युवाओं की भूमिका अहम होगी और इन्हीं युवाओं के दम पर युवा मोर्चा राजनीति में बदलाव लाएगा।

'जुड़ेगा युवा- बदलेगा भारत' के नारे के साथ मोर्चा इस अभियान की शुरूआत करने जा रहा है। युवाओं को जोड़ने के लिए सम्मेलन, सैमिनार, रैली इत्यादि आयोजित किये जायेंगे। ■

पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ श्री मोदी का प्रेरक वार्तालाप

भारत को शक्तिशाली बनाने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनी मानव संसाधन विकास की उपेक्षा

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जुलाई को पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के समारोह में ऐसे राष्ट्रीय मानव संसाधान विकास के आयोजन की हिमायत की जो भारत के युवाओं के सामर्थ्य का विश्व को साक्षात्कार कराए। श्री मोदी ने अपनी प्राचीन शिक्षा की महान विरासत में गुरुकुल से विश्वकुल की यात्रा में निहित मानव संसाधन विकास की महिमा को राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को शिक्षित करने के लिए उजागर करने की जरूरत पर बल दिया।

महाराष्ट्र के पूना में 128 सोसायटियों द्वारा संचालित फर्ग्यूसन कॉलेज के 1500 विद्यार्थियों के समक्ष "राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका" विषय पर प्रेरक वार्तालाप किया। इसी कॉलेज में आजादी की जंग के सशक्त क्रांतिकारी वीर विनायक दामोदर सावरकर ने भी पढ़ाई की थी। श्री मोदी ने हॉस्टल के उस कमरे का भी जायजा लिया जहां रहकर सावरकर ने पढ़ाई की थी, इसके अलावा उन्होंने कॉलेज परिसर में 101 वर्ष पुराने एमफीथियेटर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने वर्तमान शिक्षा पद्धति में धूल-धुसरित हो चुके युवाओं के शक्ति-सामर्थ्य के अरमानों के मद्देनजर इसमें आमूल एवं समयानुकूल परिवर्तन के विविध पहलुओं का विश्लेषण किया।

वीर सावरकर जैसे देशभक्त महापुरुषों ने फर्ग्यूसन कॉलेज की 125 वर्ष पुरानी पवित्र भूमि की विरासत में जीवन निर्माण के लिए जो प्रेरणा दी, उन ऐतिहासिक स्मृतियों से सराबोर मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। फर्ग्यूसन कॉलेज के युवा विद्यार्थियों के साथ इस वार्तालाप के लिए सोशल मीडिया के फेसबुक के जरिए तकरीबन ढाई हजार नौजवानों से प्राप्त सुझावों और राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति के विचारों का गौरवपूर्ण जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भर के युवाओं में देश के लिए कितने नये विचार और अरमान है उसका साक्षात्कार हुआ है। जिस देश के युवा अपने सामर्थ्य से देश के भविष्य के लिए कुछ कर गुजरने की प्रतिबद्धता जताते हैं, यह इस बात का परिचायक है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व की समस्याओं के हल के लिए यही युवा शक्ति अपना मिजाज

बतलाएगी।

उन्होंने कहा कि देश में आज निराशा का वातावरण है, लेकिन यही भारत भूमि बहुरत्ना वसुंधरा है और निराशा की कोई वजह नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य के लिए शक्ति-संपन्न है। गुलामी के कालखंड में भी लोकमान्य तिलक ने, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, का नारा दिया था। आजादी के बाद हम राष्ट्र निर्माण की स्वाभिमान की शिक्षा की दिशा भूल गए और युवा शक्ति के सामर्थ्य को दुनिया के समक्ष पेश करने के लिए मानव संसाधन की महिमा को उजागर नहीं किया।

भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन के लिए भारतीय गुरुकुल परंपरा की महान विरासत के सिद्धांतों को अपनाने की हिमायत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारे पास गुरुकुल से विश्वकुल की यात्रा और उपनिषद से उपग्रह तक की शिक्षा यात्रा की महान विरासत है। समूची मानव संस्कृति की विकास यात्रा में 2600 साल की शिक्षा-दीक्षा के क्षेत्र में 1800 वर्ष तक निरंतर हिन्दुस्तान का सम्मानित प्रभाव दुनिया में रहा है। नालंदा, तक्षशिला और पश्चिम में स्थित गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय का शिक्षा का इतिहास रहा है। लेकिन 800 वर्ष के गुलामी के कालखंड में हमने यह गौरव खो दिया और आजादी के बाद हमारी शिक्षा मानव संसाधन विकास (मेन मेकिंग) के बजाय 'मनी मेकिंग' मशीन कैसे बन गई? हमारे पास शांति निकेतन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और गुजरात विद्यापीठ जैसी संस्थाएं मौजूद हैं, जो हमारे महापुरुषों ने आजादी के पहले ही स्थापित की थीं और उसमें शासन व्यवस्था को कोई योगदान नहीं था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आजादी के बाद के शासकों ने क्यों हमारे महापुरुषों के शिक्षा के उत्तम माध्यम के सपने की पूरी तरह से उपेक्षा की।

श्री मोदी ने कहा कि आज केरल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है। वजह यह कि, नारायण गुरु ने 100 वर्ष पहले समाज को शिक्षा के अभियान के लिए प्रेरित कर उत्तम शिक्षा को महत्व बताया। उन्होंने कहा कि, "मैं आधुनिकता का पक्षधर हूं, पश्चिमीकरण का नहीं। मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, यही हमारी शिक्षा का आधार होना चाहिए।" हमारे युवाओं की बौद्धिक संपदा सूचना-प्रौद्योगिकी-आईटी के प्रभाव से दुनिया को चकित कर रही है, तो फिर निराशा क्यों? 21वीं सदी ज्ञान युग की है, तो फिर भारत इस सदी में 65 फीसदी युवा शक्ति के सामर्थ्य से विश्व गुरु क्यों नहीं बन सकता?

दक्षिण कोरिया जैसा छोटा देश ओलंपिक खेलों का सफल आयोजन कर दुनिया के शक्ति-संपन्न देशों की कतार में गौरव के साथ खड़ा हुआ, वहीं हमने कॉमनवेल्थ खेलों में भ्रष्टाचार के जरिए देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। क्या 120 करोड़ की आबादी का देश सिर पर हाथ रख यूं ही बैठा रहेगा? राष्ट्र निर्माण के लिए मानव संसाधन विकास पूर्व आवश्यकता है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? राष्ट्र निर्माण की कोई परवाह सरकार को नहीं है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में चीन और भारत के बीच स्पर्धा है।

1978 में VISION बनाते हुए शिक्षा व्यवस्था के लिए मानव संसाधन विकास के चार-पांच क्षेत्रों को तय कर वर्ष 2000 तक विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में चीन के 40 विश्वविद्यालयों को स्थान दिलाने की योजना बनाई और दस वर्ष में ही चीन ने 32 विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बना दिया। चीन ने शिक्षा का रोड मैप तैयार किया है। सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी का 20 फीसदी बजट शिक्षा के क्षेत्र को आवंटित किया, जबकि भारत आज जीडीपी का महज 4 फीसदी ही शिक्षा के लिए आवंटित करता है। अनुसंधान-पीएचडी के क्षेत्र में दस वर्ष पहले चीन और भारत में समान संख्या थी, वहीं आज चीन के पास भारत से सात-आठ गुना अधिक रिसर्चर स्कॉलर पीएचडी हैं।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में रिसर्च-पीएचडी करने वाले तेजस्वी स्कॉलरों का कोई अधिकृत डाटा मौजूद नहीं है, उनके संशोधन दस्तावेज उपेक्षित पड़े हैं। जबकि विदेशों में यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलरों के दस्तावेजों को सरकार की नीति निर्धारण प्रक्रिया में ध्यान में लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई देश संशोधन को प्राथमिकता नहीं देगा तो विकास में ठहराव आ जाएगा। हमें समयानुकूल परिवर्तन के लिए शिक्षा, मानव संसाधन विकास और संशोधन को प्राथमिकता देनी ही होगी। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में पहली फार्मेसी कॉलेज 50 वर्ष पूर्व गुजरात में दीर्घकृष्टा लोगों ने शुरू की, तो आज गुजरात फार्मेसी उद्योग के क्षेत्र में देश में अग्रसर बन गया है। भारत का कोई पड़ोसी उसका मित्र नहीं है।

भारत की युवा शक्ति रक्षा संसाधनों के लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं की जाती, ऐसा सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा संसाधनों के निर्माण के लिए भारत के इंजीनियरों को अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर देने की क्या व्यवस्था है। भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सदियों से अनेक स्थल मौजूद हैं लेकिन टूरिज्म विकास के लिए मानव संसाधन विकास का कोई आयोजन ही नहीं किया गया।

सरदार सरोवर नर्मदा बांध में सैलानियों पर लगे प्रतिबंध को उठाने से पांच लाख सैलानियों के वहां उमड़ने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जड़वत् मानसिकता को बदलने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान भारत की कृषि यूनिवर्सिटियां कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं हाई एग्रोटेक एजुकेशन की दिशा में किसानों को प्रेरित करती है। गुजरात सरकार और केन्द्र सरकार की मानसिकता में अंतर का मार्मिक उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पॉवर (सत्ता) की फिक्र है और हम जनता को एम्पॉवर (सशक्तिकरण) करने की चिंता करते हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए गुजरात ने रक्षाशक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ ही साइबर क्राइम डिटेक्शन के लिए दुनिया की पहली फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित की है। जबकि देश में हरेक क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की उपेक्षा हो रही है।

भारत में जिस गति से शहरीकरण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अर्बन मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मानव संसाधन विकास की प्लानिंग कहां है। देश को कहां ले जाना है? उन्होंने कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए मानव संसाधन विकास की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि आज नई पीढ़ी के उत्तम नागरिक तैयार करने के लिए उत्तम शिक्षकों की जरूरत है। लेकिन उसके मानव संसाधन विकास की हालत क्या है।

भारत विश्वगुरु था क्योंकि उसके पास उत्तम गुरु परंपरा थी। हमारा शिक्षक विश्व में सांस्कृतिक राजदूत बन सकता है, ऐसे उत्तम शिक्षकों के निर्माण के लिए गुजरात ने टीचर्स यूनिवर्सिटी शुरू की है। हम विश्व को उत्तम शिक्षकों की भेंट देने का सपना क्यों नहीं साकार कर सकते।

भारत के दो तिहाई हिस्से में समुद्री तट है, लेकिन विश्व व्यापार के इस युग में पोर्ट मैनेजमेंट, मरीन इंजीनियरिंग जैसे मानव संसाधन विकास का योजना कहीं नजर नहीं आता। देश में सबसे कम बेरोजगारी गुजरात में है, क्यों? क्योंकि गुजरात ने स्किल डेवलपमेंट के जरिए हुनरवान प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की महिमा ऐसी होनी चाहिए जो वसुधैव कुटुंबकम और ब्रह्मांड को परिवार मानने वाली शिक्षा-दीक्षा देने का सामर्थ्य रखती हो।

समाज शक्ति के आधार पर हमें राष्ट्र निर्माण के लिए सामर्थ्यवान मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देनी होगी। ■

संकट में फंसो तो बात करो सेक्युलरिज्म की!

✍ रविशंकर प्रसाद

कांग्रेस कभी भी इतिहास से कोई सबक नहीं लेती है। जब कभी भी वह अपनी काली करतूतों, भ्रष्टाचार और कुशासन के खराब रिकार्ड के कारण कठघरे में खड़ी हो जाती है तो तुरंत छद्म-सेक्युरिज्म की आड़ में छिप जाती है क्योंकि उसके पास अपनी उपर्युक्त कारगुजारियों का कोई जवाब नहीं होता है।

कांग्रेस कभी भी इतिहास से कोई सबक नहीं लेती है। जब कभी भी वह अपनी काली करतूतों, भ्रष्टाचार और कुशासन के खराब रिकार्ड के कारण कठघरे में खड़ी हो जाती है तो तुरंत छद्म-सेक्युरिज्म की आड़ में छिप जाती है क्योंकि उसके पास अपनी उपर्युक्त कारगुजारियों का कोई जवाब नहीं होता है।

जब हम 1970 के दशक में बिहार में जेपी आंदोलन के साथ सक्रिय हुए तो कांग्रेस ने उन्हें साम्प्रदायिक नेता का नाम दे दिया जो भारत को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ काम करते हैं। कुछ वामपंथी दलों ने तो जयप्रकाश नारायण को फासीवादी का नाम तक दे दिया था। जल्द ही, उस समय इन्दिरा गांधी ने इमर्जेसी लागू कर दी, विपक्षी लोगों को गिरफ्तार किया, प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी और जिसने भी इन्दिरा गांधी के शासन के खिलाफ आवाज उठाई उसे निर्ममता के साथ कुचल दिया गया। तब भी यही बात लोगों को समझाई गई थी कि इसका औचित्य सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों को बनाए रखना है, हालांकि सच्चाई यही थी कि इन्दिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमर्जेसी लगाई थी। 1977 के आम चुनावों में, लोगों के भारी आक्रोश होने के बावजूद भी कांग्रेस का यही कहना था कि वही भारत को बचा सकती है और साम्प्रदायिक शक्तियों को परास्त कर सकती है। उस समय उत्तरी भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था। जब बोफोर्स मुद्दे ने राजीव गांधी के नेतृत्व को गम्भीर संकट में डाल दिया तो फिर से कांग्रेस ने 1989 के लोक सभा चुनावों में वही सेक्युलर साम्प्रदायिक कार्ड खेला। फिर भी उसे बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। इसी कार्ड को उसने 1990 के दशक में भी भाजपा के खिलाफ आजमाया, फिर भी वह भाजपा की प्रगति को रोक नहीं पाई।

नि:संदेह, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा-नीत एनडीए का शासन सदैव मील का पत्थर बन कर याद किया जाता रहेगा।

आज, कांग्रेस-नीत यूपीए के शासन की विश्वसनीयता पूरी तरह से निम्न स्तर पर खड़ी है। भ्रष्टाचार, शासन की बेहद कमी, मुद्रास्फीति, संवैधानिक संस्थानों, विशेष रूप से सीबीआई का दुरूपयोग आज की इस केन्द्र सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी हुई है। हर दिन बीतने पर लोगों के मन में यही भाव पुष्ट होता जाता है कि कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार है। अब तो हमें यह भी याद नहीं रहता कि इस सरकार में कितने असंख्य घोटाले हुए क्योंकि ये घोटाले तो आए दिन होते ही रहते हैं। किसी को पता नहीं होता कि अगला घोटाला कब फूट पड़े। विपक्ष, मीडिया के भारी विरोध और न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद भी कांग्रेस ने एक भी घोटाले की निष्पक्ष जांच नहीं होने दी।

भारत की अर्थव्यवस्था आखिरी दम ले रही है। मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे को छोड़कर, सभी कुछ तो गिरावट की दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। अप्रैल की औद्योगिक वृद्धि दर के अंकों को गिरावट के स्तर पर संशोधित करते हुए इसे 2.3 से नीचे 1.9 प्रतिशत पर लाया गया। सम्पूर्ण विकास दर भी 5 प्रतिशत से कम रह सकती है।

यहां तक कि अब तो भारतीय भी भारत में निवेश करने से परहेज कर रहे हैं। कड़ा विरोध होने के बावजूद भी एफडीआई को रिटेल बाजार में लाया गया है। फिर भी 10 महीने से अधिक का समय गुजरने पर भी इस क्षेत्र में निवेश नहीं हो पाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास राजनीति में फंस गई है क्योंकि हर पार्टी को इसका समर्थन करना पड़ता

है। इस क्षेत्र में एनडीए का शानदार रिकार्ड रहा है। फिर भी यूपीए ने इसका गुड़-गोबर कर डाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र को बुरी तरह झटका लगा है क्योंकि लाइसेंस देने के मामलों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

'कोलगेट' अर्थात् कोयला घोटाले में विद्युत क्षेत्र संकट में पड़ गया है। एनडीए सरकार की एक और असाधारण उपलब्धि राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम भारी भ्रष्टाचार, विलम्ब तथा पारदर्शिता की कमी के कारण विध्वंसता की स्थिति तक पहुंच गया है। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का एक और बड़ा वाहक होता है, परन्तु यह भी भ्रष्टाचार, पक्षपात और राजनैतिक मुद्दों और स्पष्टता के अभाव की दलदल में फंस कर रह गया है।

अच्छी अर्थव्यवस्था और स्वच्छ राजनीति के बीच सुशासन ही एक मात्र कड़ी हुआ करता है, परन्तु यह कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार में सबसे बड़ी कैज्युलटी बन गया है। ऐसा क्यों है कि जब राष्ट्रीय विकास दर लगभग 5 प्रतिशत पर पहुंची हुई है तो भाजपा शासित लगभग सभी राज्यों में- गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोआ- बार-बार 10 प्रतिशत से अधिक दर पर बनी हुई है?

इसका स्पष्ट उत्तर इन राज्यों का सुशासन है। आज, सोनिया गांधी और मनमोहन, के संयुक्त नेतृत्व पर विश्वास का गम्भीर अभाव और विश्वसनीयता का संकट बना हुआ है।

यदि भारत के लोग ही भारत में अपना रूपया निवेश नहीं करना चाहते हैं तो विदेशी क्यों अपने डालरों और पाउण्डों को भारत में निवेश करेंगे?

इस महत्वपूर्ण बात का जवाब कांग्रेस नहीं देती है क्योंकि उन्हें पता है कि इसका कोई जवाब है ही नहीं।

अगला चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा अर्थात् ये मुद्दे होंगे- भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, बढ़ती बेरोजगारी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर छाया घोर संकट, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों में भारी निराशा का भाव। कांग्रेस को मालूम है कि इन विफलताओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है, इसलिए वह फिर से सेक्युलर-साम्प्रदायिकता का कार्ड खेलने पर तुली है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी का रिकार्ड बेहद संदिग्ध है। देश के विभिन्न भागों में हुए दंगों के अलावा, जिस निर्लज्ज ढंग से 80 के दशक में हुए सिख नरसंहार के नेताओं को बचाने और छुड़ाने की कोशिश की जाती रही है, वह तो सर्वविदित है ही। कांग्रेस को सेक्युलरिज्म पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है ही नहीं।

भारत सेक्युलर है क्योंकि इसकी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत सेक्युलर है। 2013 का भारत एक अलग भारत है, जो अपनी ताकत के प्रति विश्वसनीय और निश्चितता रखता है, जिसे अपने महान मानव संसाधनों का पता है, जिसमें अधिकांश युवा है, जो देश के विकास की महत्वाकांक्षा रखते हैं।

आज का भारत विकल्प के रूप में भाजपा और नरेन्द्र मोदी की ओर निहार रहा है। आज वह सर्वाधिक प्रिय हैं, जैसा कि विभिन्न लोकप्रिय मत सर्वेक्षणों से दिखाई पड़ता है, जिनमें वह राहुल गांधी से लगभग तिगुनी लोकप्रियता हासिल किए हुए हैं। भले ही कांग्रेस को नरेन्द्र मोदी से नफरत करने की बीमारी लगी हो, परन्तु गुजरात की जनता ने उन्हें बार-बार जिताया है। दंगे कहीं भी हों, वे दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं और दोषियों को अवश्य दण्ड मिलना चाहिए।

परन्तु, आज तो गुजरात में हर तरफ शांति, प्रगति, समृ) और चहुंओर विकास का दृश्य दिखाई पड़ता है, जहां पिछले 10 वर्षों से कोई दंगा नहीं हुआ है। कांग्रेस को स्वयं से यह प्रश्न करना आवश्यक है कि उनके लगातार नफरत का मिथ्या प्रचार करने के बावजूद भी नरेन्द्र मोदी की असाधारण लोकप्रियता क्यों बढ़ती जा रही है। इसके पीछे है उनका अखण्डता के प्रति अटल विश्वास, सुशासन का शानदार रिकार्ड और नेतृत्व की शक्ति।

भारत के लोग परिवर्तन के प्रति लालायित हैं। कांग्रेस वही सेक्युलर-साम्प्रदायिकता का विभाजनकारी पुराना नारा लगा रही है। वह पहले भी विफल हो चुकी है और आगे भी विफल होकर रहेगी। ■

(लेखक राज्यसभा में भाजपा के उपनेता हैं)

अच्छी अर्थव्यवस्था और स्वच्छ राजनीति के बीच सुशासन ही एक मात्र कड़ी हुआ करता है, परन्तु यह कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार में सबसे बड़ी कैज्युलटी बन गया है। ऐसा क्यों है कि जब राष्ट्रीय विकास दर लगभग 5 प्रतिशत पर पहुंची हुई है तो भाजपा शासित लगभग सभी राज्यों में- गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोआ- बार-बार 10 प्रतिशत से अधिक दर पर बनी हुई है? इसका स्पष्ट उत्तर इन राज्यों का सुशासन है। आज, सोनिया गांधी और मनमोहन, के संयुक्त नेतृत्व पर विश्वास का गम्भीर अभाव और विश्वसनीयता का संकट बना हुआ है।

नीतियों की नाकामी

✍ संजय गुप्त

आखिरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लंबे समय बाद अर्थव्यवस्था की समस्याओं पर अपना मौन तोड़ा, लेकिन उद्योग चैंबर एसोचैम की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा उससे शायद ही उन सवालों का समाधान हो सके जो संप्रग सरकार की शिथिलता को लेकर लंबे समय से उठ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये की लगातार घटती कीमत के साथ ही अर्थव्यवस्था कुछ नई समस्याओं से घिरती गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधे रखना ही बेहतर समझा। यह आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक आलोचना का जवाब देने के लिए संप्रग सरकार के पिछले कार्यकाल को जोड़ते हुए यह सिद्ध करने की कोशिश की कि उनकी सरकार में आर्थिक प्रगति की रफ्तार राजग के शासनकाल से बेहतर रही है। यह ठीक नहीं, क्योंकि पिछली सरकार के गठबंधन का स्वरूप अलग था और दूसरे तब के आर्थिक हालात भी अलग थे। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस हालत में पहुंच गई है उसके लिए संप्रग सरकार की निष्क्रियता ही जिम्मेदार है।

प्रधानमंत्री चाहे जैसे दावे करें, सच्चाई यह है कि संप्रग सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में नाकामी का ही इतिहास रचा है। अपने इस कार्यकाल की शुरुआत से ही सरकार पर सामाजिक क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का फितूर सा सवार है। राजनीतिक रूप से सरकार की इस प्रतिबद्धता के कुछ उचित आधार दिखते हैं, क्योंकि पिछड़े-वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के नाम पर चलाई जाने वाली योजनाएं वोट बैंक बटोरने का माध्यम बनती हैं, लेकिन किसी ने यह देखने-समझने की आवश्यकता नहीं महसूस की कि उद्योग एवं कृषि की उत्पादकता में कमी आने के कैसे दुष्परिणाम देश को भोगने पड़ेंगे? वोट बैंक के लिए आम जनता को लुभाने के उद्देश्य से आरंभ की गई योजनाओं पर भारी-भरकम धनराशि खर्च किए जाने से न केवल बजट घाटा बेलगाम होता गया, बल्कि पूरा आर्थिक माहौल ही अस्त-व्यस्त होता चला गया। संप्रग सरकार के नीति-नियंताओं ने यह समझने से इन्कार किया कि उद्योगों और आधारभूत ढांचे को प्रोत्साहन देने से ही रोजगार का सृजन होता है और विकास को गति मिलती है। इस सरकार ने न तो आधारभूत ढांचे में निवेश किया और न ही उद्योगों की समस्याओं पर ध्यान दिया। उद्योगों की रीढ़ मानी जाने वाली बिजली के ढांचे की बदहाली इसका प्रमाण है कि किस तरह सरकार ने उद्योगों की बुनियादी आवश्यकता की भी अनदेखी की।

मौजूदा आर्थिक संकट की बुनियाद संप्रग सरकार के पिछले कार्यकाल में ही पड़ गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नाम पर आरंभ की गई मनरेगा कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर सरकारी कोष की बर्बादी का माध्यम बन गई, क्योंकि उसके तहत जो कार्य कराए गए वे अस्थाई थे और उनसे आधारभूत ढांचे के विकास में कोई मदद नहीं मिली। गढ्डे और तालाब खोदने जैसे कार्यों से भले ही ग्रामीण आबादी को रोजगार पाने के कुछ अवसर मिल गए हों, लेकिन इनसे बुनियादी ढांचे की दशा सुधारने में कोई मदद नहीं मिली। मनरेगा का एक विपरीत प्रभाव शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर पड़ा। ग्रामीणों ने शहरों में आना बंद कर दिया। परिणामस्वरूप उद्योगों की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित हुई और अर्थव्यवस्था की कठिनाइयां कहीं अधिक बढ़ गई। यदि मनरेगा के धन को आधारभूत ढांचे के विकास में खर्च किया जाता तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार भी मिलता है और अर्थव्यवस्था का विकास भी होता। इसके विपरीत सरकार ने मुफ्त में पैसा बांटने की नीति को अपने लिए मुफीद माना। अब समस्या यह है कि इस नीति के दुष्परिणाम सामने आने के

यह आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक आलोचना का जवाब देने के लिए संप्रग सरकार के पिछले कार्यकाल को जोड़ते हुए यह सिद्ध करने की कोशिश की कि उनकी सरकार में आर्थिक प्रगति की रतार राजग के शासनकाल से बेहतर रही है। यह ठीक नहीं, क्योंकि पिछली सरकार के गठबंधन का स्वरूप अलग था और दूसरे तब के आर्थिक हालात भी अलग थे। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस हालत में पहुंच गई है उसके लिए संप्रग सरकार की निष्क्रियता ही जिम्मेदार है।

बावजूद सरकार शुतुरमुर्गी रवैया अपनाए है।

एसोचैम में प्रधानमंत्री का संबोधन एक बार फिर यह स्पष्ट कर रहा है कि संप्रग सरकार अर्थव्यवस्था के संकट की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं। उनके केवल यह कह देने से बात नहीं बनने वाली कि उद्योगपति नकारात्मकता के दौर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। ऐसा लगता है कि खुद प्रधानमंत्री भी आर्थिक समस्याओं को लेकर हो रही सरकार की आलोचनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं ले रहे हैं। वह इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि विकास दर में एक प्रतिशत की गिरावट भी करोड़ों नौकरियों को प्रभावित करती है। उन्हें यह भी पता होगा कि कमजोर रुपये ने आयात बिल बढ़ाने के साथ निर्यात के मोर्चे पर भी अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। कमजोर रुपया निर्यातकों पर इसलिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि उद्योगों के सामने आधारभूत सुविधाओं का भी संकट है और वे श्रम सुधारों के अभाव से भी जूझ रहे हैं। यह हैरत की बात है कि यह सरकार केवल श्रम सुधारों की चर्चा तक ही सीमित रही। श्रम सुधारों ने भारतीय उद्योगों को किस तरह नुकसान पहुंचाया, इसे कपड़ा क्षेत्र की हालत से समझा जा सकता है। एक समय भारत कपड़े का बड़ा निर्यातक था, लेकिन आज यह पूरा बाजार बांग्लादेश और कुछ दूसरे एशियाई देशों ने हथिया लिया है। अब इसके भी प्रमाण सामने आ रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में समय पर सुधार न किए जाने के कारण मांग बढ़ने के बावजूद हमारे खेतों की उत्पादकता स्थिर बनी हुई है। यह निराशाजनक है कि जब खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती जा रही है तब कृषि उत्पादकता न बढ़ने के कारण लोगों को पेट भर खाना देने में मुश्किल पेश आ रही है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री इस स्थिति से परिचित न हों, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वह खुद इस सरकार का एजेंडा तय नहीं करते। सरकार का एजेंडा तय करती है कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी एनएसी। इस परिषद ने ही भारी-भरकम खर्च वाली अनेक सामाजिक योजनाओं की शुरुआत कराई-बगैर यह सोचे-समझे कि कृषि उत्पादकता और उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचे पर ध्यान दिए बिना इस तरह की योजनाएं शुरू करने से अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। एनएसी की दखलंदाजी के कारण ही आधारभूत ढांचे और खनन से संबंधित अनेक योजनाएं-परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ सकीं, क्योंकि उसमें शामिल पर्यावरणविदों ने प्रत्येक परियोजना में अड़ंगे लगा दिए। इन पर्यावरणविदों के समक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय भी बौना साबित हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई।

सरकार का एजेंडा तय करती है कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी एनएसी। इस परिषद ने ही भारी-भरकम खर्च वाली अनेक सामाजिक योजनाओं की शुरुआत कराई-बगैर यह सोचे-समझे कि कृषि उत्पादकता और उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचे पर ध्यान दिए बिना इस तरह की योजनाएं शुरू करने से अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। एनएसी की दखलंदाजी के कारण ही आधारभूत ढांचे और खनन से संबंधित अनेक योजनाएं-परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ सकीं, क्योंकि उसमें शामिल पर्यावरणविदों ने प्रत्येक परियोजना में अड़ंगे लगा दिए। इन पर्यावरणविदों के समक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय भी बौना साबित हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई।

अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत के लिए कहीं न कहीं सत्ता के दो केंद्र होना ही सबसे बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री ने भले ही सत्ता के दो केंद्रों वाली बात को खारिज किया हो और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हो, लेकिन कोई भी यह आसानी से देख-समझ सकता है कि मनमोहन सिंह पूरी आजादी से काम नहीं कर पा रहे हैं। संप्रग सरकार अभी भी उस प्रयोग से बाहर नहीं निकलना चाह रही है जिसे कांग्रेस के ज्यादातर नेता दबे-छिपे स्वर से असफल बता रहे हैं। कांग्रेस जैसी स्थिति में है उसमें यह संभव है कि आने वाले समय में भी सत्ता के दो केंद्रों वाला प्रयोग ही दोहराया जाए, क्योंकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सरकार संभालने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक राजनीतिक दल को यह सबक लेने की आवश्यकता है कि अगर सत्ता की बागडोर संभालने वाले व्यक्ति को निर्णय लेने की शक्ति और स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी और उसे किसी अन्य के दबाव या निर्देश में काम करना होगा तो पूरे तंत्र का बंटाधार होना तय है। यह बात जितनी केंद्र की सत्ता संभालने वाले पर लागू होती है उतनी ही राज्यों का शासन चलाने वाले पर भी। ■

(दैनिक जागरण से साभार)

बिहार ने दिखाया बच्चों को लूटने का रास्ता

✍ कंचन गुप्ता

इस दृश्य से दु:खद कुछ और नहीं हो सकता कि छोटे बच्चे दोपहर में भोजन करने लगें। इनमें से कुछ बच्चों की आयु चार साल ही थी और भोजन ही उनके स्कूल जाने का एकमात्र उद्देश्य था। बिहार के सारन जिले के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद मरने वाले गरीब परिवारों के 23 बच्चे लालच, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता के मासूम शिकार बने। उनकी त्रासद मौतों के बाद संभव है कि माता-पिता अपने बच्चों का नाम स्कूल में लिखवाने से हतोत्साहित हों। जिन बच्चों ने अपने साथियों को भयंकर मौत मरते देखा है वे अब शायद ही गरम खाने के लालच में स्कूल जाना पसंद करें।

अधिकारियों की जांच में समय लगेगा और नौकरशाह अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने में माहिर हो चुके हैं। जबकि वे अपने राजनीतिक आकाओं की जिम्मेदारी से मुक्ति दिलाने में भी सहायता करते हैं। इसलिये इस भयानक घटना की बिहार सरकार द्वारा जांच से ऐसा कुछ निकलने वाला नहीं है जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनके नेतृत्व वाली सरकार के किसी अन्य मंत्री पर दोषारोपण किया जा सके क्योंकि एक बार वे फिर सेक्युलजरिज्म के मसीहा बन गये हैं। हम इस बात के लिए भी आश्वस्त हो सकते हैं कि नौकरशाह मिड डे मील योजना का ठीक से क्रियान्वयन न करने के कारण किसी दंड के भागी नही होंगे। इसके बाद हमें अव्यवस्था दूर करने के वादे और पवित्र घोषणायें सुनने को जरूर मिलेंगी।

जनता की स्मृति कुख्यात रूप से बहुत कम होने के कारण यह त्रासदी मीडिया द्वारा किसी अन्य सनसनीखेज घटना पर जाने के बाद ही भुला दी जायेगी, चाहे चौबीसों घंटे खबरों का चक्र चलाने के लिए यह घटना बनायी गयी हो या असली हो। इसके बाद लगातार बातचीत करने वाले वर्गो के बीच टेलीवीजन एंकरों के दुख और गुस्से की भावना दूसरी दिशा में मुड़ जायेंगी, जबकि ऐसे एंकर जनात की भावनायें भड़काने और उसे निम्नतम स्तर तक ले जाने के सारे प्रयास करते हैं। हमारे इस देश में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मीडिया को कोई और तमाशा दिखाने का मौका न मिले।

सरकार 23 बच्चों की मौतों के जिम्मेदार लोगों को दंड देने के बारे में क्या सोचती है? ऐसे सवालों का एक मानक जवाब यह होगा कि 'कानून अपना काम करेगा और किसी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा।' हमारे देश में कानून को मूर्ख-बनाना आसान है और इसे गलत समझने वाले स्वयं मूर्ख हैं। कुछ ही समय में स्कूल की प्रिंसिपल मीना देवी अपने छिपने की अज्ञात जगह से घर वापस आ जायेंगी। जिन्होंने खाना पकाने वाले तेल को कीटनाशकों के खाली पीपे में रखा था और खाना पकाने वाले को कठोर निर्देश दिया था कि वह तेल के रंग और गंध के बारे में कोई शिकायत न करे। मामले पर धूल छंट जाने के बाद वे फिर से अपने पेशे में लौट आयेंगी और जदयू उनको संरक्षण देगा क्योंकि विश्वास किया जाता है कि उनकी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। किसी अन्य चीज से इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकती कि ऐसी बुरी और लापरवाह महिला किसी स्कूल की प्रिंसिपल कैसे बन गयी।

यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल है जिसे कभी नीतीश कुमार से नहीं पूछा जायेगा या उनको मीडिया तथा बड़बोले वर्ग इस सवाल का जवाब देने को मजबूर नहीं किया जायेगा। अपने बच्चों को खो देने वाले गरीब मां-बाप अपनी किस्मत को

यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल है जिसे कभी नीतीश कुमार से नहीं पूछा जायेगा या उनको मीडिया तथा बड़बोले वर्ग क्षरा इस सवाल का जवाब देने को मजबूर नहीं किया जायेगा। अपने बच्चों को खो देने वाले गरीब मां-बाप अपनी किस्मत को दोष देंगे। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि सवाल पूछे नहीं जाने चाहिये। वास्तव में अनेक कमियों के जवाब पूछे जाने चाहिये जो विकास के तथाकथित 'बिहार मॉडल' से जुड़ गये हैं। यह मॉडल जनता को भिखारी बना देता है और सर्वाधिक जोखिम के शिकार, बच्चों को भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों की क्रूरता पर छोड़ दिया जाता है।

दोष देंगे। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि सवाल पूछे नहीं जाने चाहिये। वास्तव में अनेक कमियों के जवाब पूछे जाने चाहिये जो विकास के तथाकथित 'बिहार मॉडल' से जुड़ गये हैं। यह मॉडल जनता को भिखारी बना देता है और सर्वाधिक जोखिम के शिकार, बच्चों को भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों की क्रूरता पर छोड़ दिया जाता है।

उदाहरण के लिए, हमें यह सवाल पूछना चाहिये कि बिहार सरकार उन 500 करोड़ रुपयों का प्रयोग क्यों नहीं कर पायी जो स्कूलों के रसोईघरों के आधुनिकीकरण तथा मिड डे मील योजना के लिए नये बर्तन खरीदने हेतु थे। यह पैसा बैंक में जमा करने और इसका ब्याज खाने के बाद केन्द्र सरकार को वापस कर दिया गया। स्वयं को लापरवाह दिखाना अच्छी बात नहीं है और मुख्यमंत्री को इस मामले में भयंकर कमियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये तथा उनको इसके नतीजे भुगतने चाहिये।

हालांकि, यह हल्का संकेत करना भी पूरी तरह गलत होगा कि कल्याण कार्यक्रमों के खराब क्रियान्वयन की यह समस्या केवल बिहार में है। कुछ राज्यों ने मिड डे मील कार्यक्रम को लागू करने के लिए अक्षयपात्र योजना बनायी है। इनके अलावा शायद ही कोई राय दावा कर सके कि उसने दुष्ट राजनेताओं, नौकरवाहों, ठेकेदारों, शिक्षकों, झोलावालों तथा रातोंरात बनने वाले एनजीओ और उनके चमचों को इन योजनाओं से लाभान्वित नहीं किया है। यदि इससे एक दूसरे की सहायता करने वाले लालच और भ्रष्टाचार देशभर में फैल रहे हैं, इनसे हमारे समाज का असली चेहरा भी दिखाई पड़ता है।

बिहार त्रासदी सामने आने के समय मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने कहा है कि अब वह मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के प्रति गंभीरता बरतेगी। हम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राष्ट्रीय सलाहकार समिति में उनके दरबारियों को मिड डे मील अधिकार विधेयक के रूप में आगे बढ़ाने की कल्पना भी कर सकते हैं। आपराधिक रूप से लापरवाही बरतने वाला राजनीतिक नेतृत्व भूख और गरीबी का केवल मजाक उड़ा सकता है। निष्क्रिय जनता को इससे बेहतर की आशा भी नहीं करनी चाहिये।

एक राष्ट्र के रूप में हम उन बच्चों को संरक्षण और पोषण देने की चिन्ता नहीं करते हैं जो देश की जिम्मेदारी हमसे विरासत में प्राप्त करेंगे। चूंकि बच्चे मतदान नहीं करते हैं, इसलिये राजनीतिक पार्टियों की नजर में उनका कोई महत्व नहीं है, हालांकि 6 साल से कम आयु के बच्चों का जनसंख्या में लगभग पांचवा हिस्सा है।

2005-06 में कराये गये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तीसरे दौर द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में इस बिन्दु पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए हमारे बच्चों में दो बटे पांच कुपोषित हैं जो कुल कुपोषित बच्चों का 16 प्रतिशत हैं। इनमें से बहुत से बच्चे शैशवावस्था में ही दम तोड़ देते हैं। एक तिहाई से अधिक बच्चों की बढ़वार कम होती है और उनमें से तीन चौथाई रक्ताल्पता का शिकार होते हैं। असाधारण रूप से 50 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण नहीं होता है।

उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी 'उत्तम प्रदेश' के रूप में प्रचारित करने से नहीं थकती है लेकिन उसकी सरकार द्वारा मिड डे मील के रूप में दी जाने वाली उच्च कैलोरी की फौरन भोजन योग्य पंजीरी भ्रष्ट अधिकारियों की नजरों के सामने मवेशियों को खिला दी जाती है। उत्तर प्रदेश में 'पंजीरी माफिया' की इतनी पकड़ थी कि राज्य के आधे जिलों में मिड डे मील कार्यक्रम बहुत बुरी स्थिति में है। ऐसे में यह बात समझ में आती है कि इन जिलों के बच्चों में कुपोषण 50 से 70 प्रतिशत के बीच होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले से पूरे देश में मिड डे मील लागू करने पर जोर दिया है, लेकिन करने के बजाय यह कहना ज्यादा आसान है। केन्द्र सरकार के एक आंतरिक मेमोरेंडम में स्वीकार किया गया है कि समग्र बाल विकास योजना लागू करने में 30 साल का विलम्ब बहुत अधिक है, लेकिन इसके बावजूद यह भी कहा गया है कि 'भारत में बाल कुपोषण दुनिया में सबसे अधिक है।' नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की एक रिपोर्ट में मिड डे मील योजना की भयानक विफलता को रेखांकित किया गया है। इस बीच, बिहार त्रासदी सामने आने के समय मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने कहा है कि अब वह मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के प्रति गंभीरता बरतेगी।

हम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राष्ट्रीय सलाहकार समिति में उनके दरबारियों को मिड डे मील अधिकार विधेयक के रूप में आगे बढ़ाने की कल्पना भी कर सकते हैं। आपराधिक रूप से लापरवाही बरतने वाला राजनीतिक नेतृत्व भूख और गरीबी का केवल मजाक उड़ा सकता है। निष्क्रिय जनता को इससे बेहतर की आशा भी नहीं करनी चाहिये। ■

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं)

(साभार : पायनियर)

हताश कांग्रेस उतरी विरोध के लिये विरोध के हथकण्डों पर

✍ अम्बा चरण वशिष्ठ

अगले लोक सभा चुनाव तो अभी लगभग 9 मास दूर 2014 में हैं पर लगता है कांग्रेस आज ही अपनी हार मान कर विपक्ष की भूमिका में आ गई है। उस विपक्ष की जो सकारात्मक नहीं है, जो हर बात व शब्द का विरोध करना अपना नैतिक कर्तव्य समझता है, मात्र विरोध के लिये विरोध और कुछ नहीं। लोग तो यहां तक चुटकी लेने लगे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी आज कह दे कि सूर्य पूर्व से निकलता है तो कांग्रेस एक दम उग्र होकर कह देगी कि बिल्कुल झूठ, सूर्य तो पश्चिम से निकलता है।

भाजपा और गुजरात के मुख्य मन्त्री व भाजपा के चुनाव प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र मोदी के ताबड़-तोड़ राजनीतिक हमलों से कांग्रेस तो इतनी परेशान हो गई है कि घबराहट में उल्टा-पुल्टा सब कुछ बोलती जा रही है। कांग्रेस ने इण्डियन मुजाहिदीन के जन्म को गुजरात दंगों की उपज बता दिया है। ट्विटर पर एक ने चुटकी लेते हुये लिखा कि महमूद गजनवी का आक्रमण भी गुजरात दंगों की ही नतीजा था। एक तो और भी आगे निकल गया। उसने लिखा कि गजनवी इतना बड़ा दूरदर्शी निकला कि उसने कई सदी पूर्व ही गुजरात दंगों का पुर्वाभास कर लिया था कि उसने तभी इस कारण भारत पर हमला बोला दिया।

आंध्र प्रदेश भाजपा ने एक अनुकरणीय पहल की। उसने श्री मोदी की रैली में भाग लेने के इच्छुक सभी कार्यकर्ताओं व समर्थकों से प्रतीकात्मक पांच रूपये का चन्दा लेने का निर्णय किया जो सारी की सारी राशि केदारनाथ में हुई तबाही से ग्रसित लोगों को भेजी जानी है। पर विरोध के नाम पर विरोध के लिये कांग्रेस इसकी भी आलोचना करने से न चूकी।

यही कहानी है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह के उस कथन पर जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी के बढ़ते चलन से भारत की संस्कृति दूषित हुई है और युवाओं का अंग्रेजीकरण भारत के लिये खतरनाक है। कांग्रेस इस कथन के विरोध में भी तुरन्त उठ खड़ी हो गई।

श्री राजनाथ सिंह के कथन में गलत है भी क्या? यही तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य महान् नेता सदा कहते आये हैं। आज की सोनिया कांग्रेस भारत में किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हिन्दुत्वीकरण का तो सख्त विरोध करती है और अंधाधुंध अंग्रेजीकरण व पाश्चात्यकरण का स्वागत। इसलिये कांग्रेस को तो अपने नाम से 'भारतीय' शब्द को ही निकाल देना चाहिये क्योंकि आज की कांग्रेस की सोच के साथ यह मेल नहीं खाता। उसे शायद याद नहीं कि स्वतन्त्रताप्राप्ति के बाद जब बीबीसी ने महात्मा गांधी से अंग्रेजी में एक साक्षात्कार के लिये अनुरोध किया था (तब अभी बीबीसी की हिन्दी सेवा आरम्भ नहीं हुई थी) तो उन्होंने इन्कार करते हुये कह दिया था कि अब सब को बता दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है। उन्होंने अंग्रेजी का तब तक प्रयोग किया जब तक कि यह अंग्रेजों के साथ स्वतन्त्रताप्राप्ति के लिये वार्तालाप के लिये आवश्यक था।

भाषा और संस्कृति का तो मांस और नाखून का रिश्ता है। अपनी पहचान के लिये किसी भी संस्कृति व राष्ट्र की अपनी भाषा होना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपनी पहचान के लिये अपने माता-पिता, वंश-गोत्र, गांव, प्रदेश व देश का नाम जुड़ा होना। तो अपनी स्वदेशी राष्ट्रभाषा के अभाव में क्या भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण हो सकती है?

यह भी स्मरणीय है कि इजराईल राष्ट्र का उद्गम व जन्म अमरीका व पश्चिमी देशों के सहयोग व आशीर्वाद से हुआ। अंग्रेजी भाषा उनकी रग-रग

श्री राजनाथ सिंह के कथन में गलत है भी क्या? यही तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य महान् नेता सदा कहते आये हैं। आज की सोनिया कांग्रेस भारत में किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हिन्दुत्वीकरण का तो सख्त विरोध करती है और अंधाधुंध अंग्रेजीकरण व पाश्चात्यकरण का स्वागत। इसलिये कांग्रेस को तो अपने नाम से 'भारतीय' शब्द को ही निकाल देना चाहिये क्योंकि आज की कांग्रेस की सोच के साथ यह मेल नहीं खाता।

में बसी थी। फिर भी जब इजराइल राष्ट्र के निर्माण व गठन का समय आया तो उसके बानी व राष्ट्रनिर्माता डेविड बेन-गुरियन ने कहा कि अपनी अलग राष्ट्रभाषा के बिना उनका राष्ट्र अधूरा है। उन्होंने इजराइल के संविधान में अंग्रेजी भाषा को नकार कर हेब्रू व वहां की अरबी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाया। अंग्रेज तो 66 वर्ष पूर्व भारत को स्वतन्त्र कर देश छोड़ गये पर हमारी सोनिया कांग्रेस अंग्रेजी व अंग्रेजीयत की अभी भी गुलाम बनी बैठी है और उससे आजादी नहीं चाहती और जो लोग यह चाहते हैं उनका विरोध करती है।

भाषा न कोई बड़ी होती है और न छोटी। हर भाषा का अपना महत्व होता है, अपना स्थान। हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से प्यार और उस पर गर्व होता है और होना भी चाहिये। झगड़ा तो तब खड़ा होता है जब कोई एक भाषा को उत्कृष्ट और दूसरी को निकृष्ट करार देने की चेष्ठा करता है। अपनी मां हर व्यक्ति को सर्वप्रिय व श्रेष्ठ लगती है। किसी की भावना को तो तब ठेस पहुंचती है जब कोई व्यक्ति अपनी मां को तो पूजनीय और दूसरे की मां को तिरस्कार योग्य बताता है। यही अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बारे का सच है।

इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है जो विश्व में सब से अधिक बोली व समझी जाती है। विवाद तो तब खड़ा होता है जब अंग्रेजी को किसी संस्कृति विशेष के प्रचार-प्रसार व दूसरी संस्कृतियों को हीन दिखाने के लिये किया जाता है। आज अंग्रेजी का दुरूपयोग भारतीय संस्कृति को प्रदूषित करने व पाश्चात्य सभ्यता के महिमामण्डन के लिये किया जाने लगा है। यथार्थ यह है कि जब से अंग्रेजी को प्रोत्साहन व महत्व दिया जाने लगा है तब से देश में शराब, व्यभिचार, बलात्कार तथा अन्य सामाजिक बुराईयों की संख्या कई गुणा होती जा रही है। देश में भ्रष्टाचार और समाज में उच्छृंखलता को मुस्कराते हुये प्रोत्साहित करना इसी अंग्रेजिघ्यत की ही देन है।

अंग्रेजी भाषा किसी भी देश के विकास, समृद्धि व सम्पन्नता की कुंजी नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आादि योरूपीय देश व जापान, रूस और चीन आदि सब की अपनी राजभाषा है पर फिर भी विकसित व सम्पन्न हैं। फ्रांस को तो अपनी भाषा पर इतना गर्व है कि जब एक बार यूनेस्को सम्मेलन फ्रांस में हुआ और वहां के शिक्षा मन्त्री को अध्यक्षीय भाषण देना था तो उसे अंग्रेजी में नहीं फ्रेंच भाषा में दिया।

यही नहीं। एक फ्रांसीसी विद्वान ने तो अंग्रेजी भाषा की उत्कृष्टता और सम्पन्नता की ही खिल्ली उड़ाई है। उसने कहा है कि अंग्रेजी भाषा कुछ नहीं, केवल गलत लिखी (mis-spelt) फ्रांसीसी भाषा है।

भारत का आध्यात्मिक व आर्थिक वैभव, सम्पन्नता व समृद्धि तो विश्वविख्यात थी। यह न अंग्रेजों की देन है और न अंग्रेजी के ही कारण। तब तक तो अंग्रेज व मुस्लिम आक्रमणकारी आये भी न थे। सोने की चिड़िया होने के कारण ही तो भारत अफगान, मुस्लिम व अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बना। यदि उस समय का भारत मूढ़, भूखा और नंगा होता तो कौन इस देश की ओर आकृष्ट होता? और यदि मुगल आदि आक्रमणकारी किसी समृद्ध देश से आये होते तो वह अवश्य स्वदेश वापस लौट जाते जब अंग्रेजों ने उनसे राज छीन लिया, ठीक उसी तरह जैसे कि अंग्रेज अपने देश ब्रिटेन वापस चले गये जब उन्हें भारत छोड़ना पड़ा।

भारत एक सम्पन्न देश रहा है इस तथ्य की पुष्टि लार्ड मैकाले ने भी की थी। वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेवा में 1834 से 1838 तक भारत में रहे जिस समय कम्पनी का ही साम्राज्य था। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने लिखा कि भारत में उन्होंने बहुत विस्तृत प्रवास किया और उन्हें इस देश में न कहीं कोई भिखारी दिखाई दिया और न ही चोर। भारत के नैतिक मूल्यों व उसकी प्रतिभा की उत्कृष्टता से प्रभावित होकर वह यह कहने पर मजबूर हो गये कि वह नहीं समझते कि ब्रिटेन कभी इस देश पर सदैव के लिये अपने पांव जमा पाने में सफल हो पायेगा जब तक कि उसकी समृद्ध आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत को तोड़-मरोड़ न दिया जाये जो उसकी रीढ़ की हड्डी है। इसलिये उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाने पर जोर दिया जिससे कि कम्पनी की सरकार भारत में एक ऐसी वर्गश्रेणी का निर्माण कर दे जो ब्रिटिश शासकों व उन करोड़ों गुलामों के बीच की एक कड़ी का काम करे जिन पर वह शासन करते थे, एक ऐसा वर्ग जो खून व रंग में तो भारतीय हो पर अपनी रूचि, विचारों, नैतिक मूल्यों, प्रज्ञा-बुद्धि व विचारशक्ति में बिलकुल अंग्रेज।

आज का हमारा कांग्रेस नेतृत्व मैकाले के उस स्वप्न को साकार करने पर तुला है जिस उद्देश्य को न ईस्ट इण्डिया कम्पनी ही प्राप्त कर पाई और न अंग्रेज सरकार।■

(लेखक भाजपा के साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है जो विश्व में सब से अधिक बोली व समझी जाती है। विवाद तो तब खड़ा होता है जब अंग्रेजी को किसी संस्कृति विशेष के प्रचार-प्रसार व दूसरी संस्कृतियों को हीन दिखाने के लिये किया जाता है।

बिहार के विकास पुरुष की खुली पोल

बच्चों के दोपहर के भोजन के लिये स्वीकृत 463 करोड़ पांच वर्ष तक खर्च नहीं किये

✍ विकास आनन्द

जब से श्री नीतीश कुमार ने गठबन्धन धर्म में छुरा घोंप कर भाजपा से नाता तोड़ा तब से लगता है कि उनकी सरकार के बुरे दिन आ गये हैं। आये दिन कोई न कोई अप्रिय घटना घटती जा रही है। कहीं बलात्कार तो कहीं नक्सली हमला। कानून और व्यवस्था तो चरमरा गई लगती है। ऊपर से अभी पिछले सप्ताह ही कुछ स्कूलों में दोपहर के भोजन में जो दुर्घटनायें हुई उससे तो पत्थर से पत्थर दिल व्यक्ति का दिल भी दहले बिना नहीं रह सकता। एक ही दिन में छपरा जिला के एक स्कूल में दोपहर का विषैला भोजन खाने से 26 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे और अनेकों मौत से लड़ रहे हैं। एक और स्कूल में भी तीन बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। कई अन्य स्कूलों की भी ऐसी अनेक कहानियां हैं जहां स्वच्छता से खिलवाड़ हो रहा है और बच्चे कीड़े वाले चावल खाने पर मजबूर हैं। जहां भोजन बनता है वहां गन्दगी की भरमार है और कीड़े-मकोड़ों का राज है। अब हालत यह है कि बड़-बोले श्री नीतीश अब मौनी बाबा ही बनने पर मजबूर हो गये हैं। एक सप्ताह बाद जब एक टीवी चौनल पर उन्होंने अपनी जुबान खोली तो स्पष्टीकरण दिया कि एक फ्रैक्चर के कारण वह बोल न पाये थे। जनता के ज्ञान में वृद्धि हुई कि अन्य अंग में चोट के कारण भी व्यक्ति की जुबान बन्द हो जाती है। उन्होंने पीडित गांव के लिये अनेक सामाजिक कार्यक्रमों की घोषणा कर डाली मानो उससे उन घरों में बच्चों की किलकारी पुन: जीवन्त हो उठेगी ।

अपने अहंकारी कदम से श्री नीतीश कुमार बिहार की जनता का अहित कर रहे हैं।

वैसे तो श्री नितीश बिहार में विकास का बड़ा डंका बजाते हैं। उसमें बहुत सारी भागीदारी तो भाजपा की है जिसके मन्त्रियों ने अपने-अपने विभागों में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। पर वह सारा श्रेय स्वयं हड़पने का प्रयास करते हैं और इसमें अपने सहयोगियों को भी उचित श्रेय नहीं देते। दूसरी ओर इस शर्मनाक हृदयविदारक घटना पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय नीतीश सरकार उल्टे अपने राजनीतिक विरोधियों को ही दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है।

बिहार के शिक्षा मन्त्री ने तो इस दुर्घटना का सारा ठीकरा वहां की मुख्याध्यापिका के सिर फोड़ दिया और बातों ही बातों में एक गैर-भाजपा नेता की ओर इशारा कर दिया जिसके दबाव में उस मुख्याध्यापिका को उस स्कूल में लाया गया था। दूसरे शब्दों में यह उनकी स्वीकारोक्ति थी कि नीतीश कुमार सरकार सही-गलत का ध्यान किये बगैर दबाव में आकर काम करती है।

मन्त्री महोदय ने तो इसे सरकार के विरुद्ध साजिश का भी आरोप गढ़ दिया। यह भी स्वयं में ही सरकार की स्वीकारोक्ति है कि वह इतनी सशक्त व सतर्क है कि एक छोटी सी साजिश को भी विफल करने में नाकाम रही। विरोधी तो षड्यन्त्र रचते ही रहते हैं पर एक जीती-जागती सरकार का कर्तव्य है कि वह जनविरोधी साजिशों का पर्दाफाश कर उनकी हवा निकाल दे।

बिहार की त्रासदी यहीं खत्म नहीं हो जाती। दीन-दलित की हामी भरने वाली इस नितीश सरकार को केन्द्र ने पांच वर्ष पूर्व प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिये दोपहर के भोजन के लिये आवश्यक बर्तन व स्वच्छ स्थान उपलब्ध करवाने के लिये 463 करोड़ रूपये की राशि भेजी थी। पर सरकार ने इस धन का कोई सदुपयोग नहीं किया। पांच वर्ष यह पैसा सरकार के पास निठल्ला पड़ा रहा। आडिटरों ने जब आपत्ति उठाई तब भी नीतीश सरकार के कान पर जूं तक न रेंगी। अन्तत: वह इतनी बड़ी धनराशि केन्द्र सरकार को लौटाने पर मजबूर हो गई। प्रदेश के विकास के प्रति सजगता और गरीबों के प्रति इस सरकार के दिल में पीड़ा का इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है?

यह भी कोई नई बात नहीं है। कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण बिहार में बड़ी तबाही मची थी। तब गुजरात की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने प्रदेश के पीड़ितों की सहायता के लिये 5 करोड़ रूपये की सहायता राशि भेजी थी। यह राशि श्री मोदी ने न तो निजी तौर पर श्री नीतीश कुमार को भेजी थी और न ही यह उनकी अपनी निजी सम्पत्ति थी। पर जब श्री नीतीश कुमार की श्री मोदी से राजनीतिक अनबन हो गई तो गुस्से में आकर उन्होंने यह राशि श्री मोदी को लौटा दी। इस अहंकारी कदम से उन्होंने अपना नहीं, बिहार की जनता का ही अहित किया। ■

आगामी चुनावों का प्रमुख मुद्दा होगा भ्रष्टाचार!

हमारे संवाददाता द्वारा

गत 21 जुलाई को राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा है कि भ्रष्टाचार आगामी लोकसभा चुनावों में प्रमुख मुद्दा रहेगा और चण्डीगढ़ के निवासी देश से भ्रष्टाचार मिटाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि चण्डीगढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र राष्ट्रीय रूख का संकेत देती है और इस बार पूरा देश चण्डीगढ़ की और निहार रहा है कि इस शहर के मतदाता नैतिकता की उच्च भूमि पर खड़े होकर भ्रष्टाचार को मिटाने में सहायता करेंगे।

चण्डीगढ़ की भाजपा कार्यकारिणी की पहली बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री जेटली ने कहा कि आगामी लोक सभा चुनाव मात्र राजनैतिक संघर्ष नहीं होगा बल्कि यह नैतिकता और अनैतिकता के बीच 'धर्मयुद्ध' होगा। दुर्भाग्य की बात है कि चण्डीगढ़ जैसा एक महत्वपूर्ण और सम्मानीय शहर देश का इसलिए केन्द्र बिन्दु बना कि यहां के इसके निर्वाचित सांसद और पूर्व रेलमंत्री पवन कुमार बंसल का नाम भ्रष्टाचार से जुड़ा।

कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की भर्त्सना करते हुए श्री जेटली ने कहा कि सरकार भले ही सीबीआई के साथ सांठगांठ कर रही हो, परन्तु ''रेलगेट'' फोन वार्तालाप और फाइलों की आवाजाही से स्पष्ट ही एक अलग मामला दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि पूरा बंसल परिवार तैनातियों और पदोन्नतियों के मामले में एक उद्योग चला रहा था।

उन्होंने आगे कहा कि ''कांग्रेस सीबीआई का दुरूपयोग न केवल अपने मंत्रियों और अन्य कांग्रेसियों को बचाने में जुटी हुई है बल्कि वह स्वयं को सत्ता में बनाए रखने के लिए भी सीबीआई का दुरूपयोग कर रही है। जब-जब भी सरकार को संख्या जुटाने की चिंता हुई है, तब तब देखा गया है कि अचानक ही सीबीआई आय से अधिक सम्पत्ति के जांच में घिरे सपा और बसपा के नेताओं के प्रति उदार बन जाती है। सीबीआई को याद रखना होगा कि वोट सीबीआई को नहीं मिलते हैं, बल्कि लोग वोट करते हैं और स्पष्ट है कि लोगों का मन भाजपा के साथ है।

देश में फैले भ्रष्टाचार पर बात करते हुए श्री अरुण जेटली ने कहा कि लाखो-करोड़ो रूपए के 2जी, कोयला घोटाला, रेलगेट घोटाला आदि में फंस कर कांग्रेस पूंजीवाद की अंतरंग मित्र बन गई है और कांग्रेसी लोगों का नाम कर्ज देने वालों में गिना जाने लगा है। पतन की स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट भी तोड़ मरोड़कर पेश की गई है जिससे पीएमओ और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों को बचाया जा सके।

बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर अपनी निराशा जताते हुए उन्होंने कहा कि वाजपेयी सरकार के दौरान भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का केन्द्र बिन्दु माना जाता था। किन्तु, आज भारत के व्यापारी वर्ग भी देश में अपना पैसा

निवेश करने से घबराते हैं। ऐसी स्थिति में, एफडीआई में किए गए नीतिगत परिवर्तनों के बावजूद भी कोई सफलता नहीं मिली है। चालू खाते का घाटा अनियंत्रित हो गया है, परन्तु कांग्रेस है कि इस अर्थव्यवस्था को सुधारने की बजाए, वह वोट बैंक खरीदने के लिए खजाना खोल देना चाहती है और देश को सत्ता से जाते-जाते भ्रष्टाचार में डुबो देना चाहती है।

श्री जेटली ने भारत के साथ पड़ोसी देशों के साथ बिगड़ते सम्बन्धों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारी सीमाएं छिद्रिल हो कर घुसपैठ का शिकार बन गई हैं और पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्ध निकृष्टतम होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान हमारे जवानों का सिर काट देते हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैलाते है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं।

उन्होंने स्मरण कराया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से शान्ति वार्ता की शुरूआत की थी तो उसमें उन्होंने यह पूर्व शर्त रखी थी कि पाकिस्तान की धरती से भारत के प्रति किसी प्रकार का आतंकवाद नहीं होगा और पाकिस्तान ने इसे माना था। श्री जेटली ने आगे कहा कि हर मोर्चे पर विफलता की इन परिस्थितियों में, कांग्रेस के पास लोगों को प्रेरणा देने या विश्वास भरने में कोई नेतृत्व है ही नहीं और ऐसा लगता है कि वह बिना किसी नेतृत्व के राजनैतिक लड़ाई लड़ने का इरादा रख रही है।

इस अवसर पर अन्य लोगों के साथ-साथ चण्डीगढ़ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री संजय टण्डन, पंजाब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री कमल शर्मा, भाजपा विधि कार्यकारी ग्रुप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यपाल जैन तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ■

पृष्ठ 12 का शेष...

दिया, म्युनिसिपल अधिकारी जो उसके घर पर हो रहे असामान्य निर्माण पहचानने में असफल रहे, वे गुप्तचर अधिकारी जिन्होंने सूचनाओं को अपने पास ही रखा और उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अकुशलता का उल्लेख किया है जो 'कर्तव्य पालन करने से वंचित रहने के गंभीर दोषी' पाए गए।

कमीशन ने उन सैन्य अधिकरियों से बातचीत की है जो पाकिस्तानी वायुसीमा में अमेरिकी विमानों के घुसने से बेखबर रहे और पाया कि 2 मई की रात को अमेरिकियों द्वारा बिन लादेन के शव को विमान में ले जाने के 24 मिनट के भीतर पहले पाकिस्तानी लड़ाकू जेट फौरन रवाना हुआ।

रिपोर्ट कहती है यदि इसे विनम्रता से कहा जाए तो यह यदि अविश्वसनीय नहीं अपितु अकुशलता की स्थिति ज्यादा है तो विस्मयकारक है।

रिपोर्ट में उल्लेख है कि सेना की शक्तिशाली इंटर-सर्विस इंटेलीजेंस निदेशालय "ओबीएल को पकड़ने में पूर्णतया असफल'' रहा है और इसमें तत्कालीन खुफिया एजेंसी के मुखिया लेटिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की विस्तृत गवाही भी है।

Osama & compound कमीशन रेखांकित करता है कि कैसे आई. एस.आई. अधिकांशतया नागरिक नियंत्रण से बाहर ही ऑपरेट करती है। बदले में जनरल पाशा उत्तर देते हैं कि सी.आई.ए. ने सन् 2001 के बाद बिन लादेन के बारे में सिर्फ असंबद्ध गुप्तचर सूचनाएं ही सांझा की। रिपोर्ट में लिखा है कि एबटाबाद पर धावा करने से पूर्व अमेरिकियों ने बिन लादेन के चार शहरों-सरगोधा, लाहौर, सियालकोट और गिलगिट में होने की गलत सूचना दी।

जनरल पाशा को उद्धृत किया गया है कि "अमेरिकी अहंकार की कोई सीमा नहीं है''। साथ ही साथ यह कि "पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र था, यहां तक कि हम अभी भी एक असफल राष्ट्र नहीं हैं''। अल जजीरा द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में गायब गवाही सम्बन्धी पृष्ठ जनरल पाशा की गवाही से सम्बन्धित हैं। अपनी वेबसाइट पर अल जजीरा लिखता है कि संदर्भ की जांच से यह लगता है कि गायब सामग्री देश के सैन्य नेता जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा "सितम्बर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका से की गई सात मांगों की सूची है।

पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों ने अल जजीरा की रिपोर्ट की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

सोमवार को भी, दि एसोसिएटिड प्रेस ने प्रकाशित किया है कि अमेरिका के स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन के शीर्ष कमांडर ने आदेश दिए कि बिन लादेन पर हमले सम्बन्धी सैन्य फाइलें रक्षा विभाग के कम्प्यूटरों से साफ कर दी जाएं और सी.आई.ए. को भेज दीं जहां उन्हें ज्यादा आसानी से जनता की नजरों से बचाया जा सकता है।

वाशिंगटन से इरिक सम्मिट ने इस हेतु सहयोग किया। ■